an>

title: Further Discussion on r esolution regarding scheme for development of technical skills amongst youth to enable them to contribute towards making India a modern country and achieving the goal of 'Make in India' moved by Shri C.R. Patil on 19th December, 2014 (resolution withdrawn).

HON. DEPUTY SPEAKER: The House will take up further discussion on the following Resolution moved by Shri C.R. Patil on the 19th December, 2014 :--

> "Keeping in view the commitment of the Union Government to promote the development of our country, which can be effectively realized through 'skill development', this House urges upon the Government to frame a comprehensive scheme providing for development of such technical skills amongst youth as would enable them to contribute towards making India a modern country and in achieving the goal of 'Make in India'."

श्री सी.आर. पाटील **(**नवसारी**) :** उपाध्यक्ष महोदय, आपका बहुत-बहुत धन्यवाद। मैंने यह प्रस्ताव पहले ही प्रस्तुत किया हुआ है कि हमारे देश के विकास को बढ़ावा देने के लिए संघ सरकार की प्रतिबद्धता चाहिए ,जैसे कौशल विकास के माध्यम से इसे प्रभावित रूप से साकार किया जा सकता है। इसे देखते हुए यह सभा सरकार से आग्रह करती है कि वह युवाओं में ऐसे कौशल विकास उपलब्ध कराने वाली व्यापक योजना बनाये, जिससे उन्हें भारत को आधुनिक देश बनाने और भारत बनाओ के लक्ष्य को पूरा करने की दिशा में सहायता मिलेगी।

15.39 hrs (Shri Anandrao Adsul *in the Chair*)

माननीय सभापति जी, इस विषय पर मैं कहना चाहता हूं कि हमारे आदरणीय प्रधान मंत्री श्री नरेन्द्र मोदी जी ने 15 अगस्त को लाल किले से अपने भाषण से देश के युवाओं को एक संदेश दिया था, एक दिशा दी थी और युवाओं को कैसे आगे बढ़ना चाहिए, यह भी बताया था। उन्होंने कहा था कि भारत देश में कुल जनसंख्या के 65 प्रतिशत लोग 35 वर्ष की आयु से कम हैं। उन्हें अगर विविध क्षेत्र में कुशलता हासिल करनी है, तो सरकार उसके लिए मदद करने को तैयार है। हमारे देश के युवाओं को कुशल ड्राइवर, प्लम्बर, इलैक्ट्रीशियन और कुक इत्यादि क्षेत्रों में अच्छा मौका मिल सकता है।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह भी बताया था कि कुशल प्लम्बर, इलैक्ट्रीशियन इंजीनियर के बराबर पैसा कमा सकता है। आज देश में युवाओं ने आईटी क्षेत्र में क्रांति की है। विश्व में हमारे देश के युवा आईटी क्षेत्र के साथ जुड़े हुए हैं। हमारे देश की युवा जनसंख्या विश्व को कुशल कारीगर दे सकती है। विश्व की रिक्वायरमेंट को पूरा करने की क्षमता देश के युवाओं में है। विश्व में स्कील वर्कर्स की बहुत डिमांड है। इसे पूरा करने के लिए हमारे देश के युवा सक्षम भी हैं और माननीय प्रधानमंत्री उनके लिए पूरी तरह से व्यवस्था करने के लिए तैयार हैं। अगर हमारे पास स्किल वर्कर्स होंगे तो अलग-अलग इंडस्ट्री की प्रोडक्शन में बढ़ावा होगा, अच्छी क्वालिटी का सामान पैदा होगा। हम इससे ज्यादा दाम ले सकेंगे और ग्राहकों को अच्छी क्वालिटी का माल दे सकेंगे। इससे युवाओं में ज्यादा रोजगार की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। देश के नौजवान उम्मीद लगाकर बैठे हैं कि उनको कौशल के आधार पर काम मिले, इसलिए वह कौशल सीखना चाहता है। आदरणीय प्रधानमंत्री जी जब गुजरात के मुख्यमंत्री थे, तब उन्होंने अलग-अलग एलोकेटिड फंड्स का 97 परसेंट उपयोग किया था। यही कारण है कि पूरे देश में जो सौ नौकरियां पैदा होती थीं, उसमें से 71 परसेंट नौकरियां गुजरात में पैदा होती थी और युवा गुजरात की तरफ आकर्षित होते थे। यह एक इतिहास बना है। आज भी गुजरात का युवा नौकरी ढूंढने किसी और राज्य में नहीं जाता है क्योंकि उसके लिए गुजरात में ही इतनी उपलब्धियां हैं कि उसे किसी और राज्य की तरफ देखने की आवश्यकता नहीं पड़ती है। गुजरात में कौशल बढ़ा है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह सम्मान गुजरात को दिलाया है। यही कारण है कि देश का युवा माननीय प्रधानमंत्री जी की तरफ आस लगाकर बैठा है। उन्हें विश्वास है कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में जैसा किया है, वैसे ही देश में युवाओं के लिए जॉब क्रिएट करेंगे और युवाओं को किसी और राज्य में रोजगार की तलाश में जाना नहीं पड़ेगा।

महोदय, अगर हमें ड्राइवर चाहिए तो स्किल ड्राइवर उपलब्ध नहीं होता है। अगर अच्छा प्लम्बर चाहिए होता है तो वह भी उपलब्ध नहीं होता है। हमें अच्छा कुक भी नहीं मिलता है। दिल्ली की ही बात लीजिए, अगर कोई कुक चाहिए तो नहीं मिलता है। हमें अच्छा पुजारी की भी जरूरत होती है। अगर उसके पास स्किल है तो वह पूजा का अच्छा काम कर सकता है। माननीय प्रधानमंत्री जी ने गुजरात में आदिवासी विस्तार के लिए युवाओं को ड्राइवर की ट्रेनिंग देने के लिए ट्रेनिंग सैंटर शुरु किए थे। गुजरात में ट्रेनिंग सैंटर से ट्रेनिंग लेने वालों की बहुत डिमांड है। आईएएस अधिकारी, आईपीएस अधिकारी वहीं के ट्रेंड ड्राइवर को रखना चाहते हैं। अगर ड्राइवर के पास स्किल नहीं है तो दुर्घटना की संभावना बढ़ जाती है। अगर वह ट्रेंड है तो वह अच्छी तरह से गाड़ी चलाएगा और बैठने वाला सुरक्षित रहेगा। सुरक्षा अत्यंत आवश्यक है यही वजह है कि स्किल ड्राइवर की डिमांड रहती है। गुजरात में यह पासिबल हो सका है क्योंकि यहां ट्रेनिंग सैंटर बना हुआ है।

गुजरात में सूरत शहर में करीब दस लाख से ज्यादा टैक्सटाइल कारीगर हैं। आज भी उन्हें किसी प्रकार की ट्रेनिंग नहीं मिलती है। पूरे देश के 70 परसेंट कपड़े का प्रोडक्शन सूरत में होता है। उनकी मौलिकता की वजह से नए डिजाइन का कपड़ा तैयार होता है, जो महिलाओं को आकर्षित करता है। विदेशों में बहुत कपड़ा यहीं से ही जाता है। इंडस्ट्री में जो काम करने वाले वर्कर्स हैं तो कम कॉस्ट में ज्यादा उत्पादन लाने की क्षमता वे रखते हैं क्योंकि उनके पास अनुभव है। सूरत में टैक्सटाइल में मौलिकता के आधार पर नया विकास होता ही है परंतु स्किल डवलपमेंट के साथ जो किया जाए तो सोने पर सुहागा हो सकता है। पूरे देश के लोगों को सस्ता कपड़ा मिल सकता है। अच्छी क्वॉलिटी भी मिल सकती है। आज भी टैक्सटाइल के कारीगरों को 14-15 हजार रुपये की तनख्वाह मिलती है। अगर उन्हें ठीक से ट्रेनिंग दी जाए तो उनके पगार में भी बढ़ोतरी हो सकती है। टैक्सटाइल इंडस्ट्री के साथ साथ सूरत डाइमंड इंडस्ट्री के नाम से भी जाना जाता है। सूरत शहर में गुजरात सरकार ने ड्रीम सिटी बनाने के लिए एक प्रोजेक्ट डिवलेअर किया है। उसके अंदर करीब दो साल में डायमंड वर्क शुरु हो जाने की संभावना है और लगभग लाखों लोगों को वहां पर नयी नौकरी मिलने की संभावना खड़ी हो गई है।

केन्द्र सरकार द्वारा भी इस परियोजना के लिए सभी प्रकार की सहायता मिल रही है और सूरत में तैयार होने वाला डायमंड पूरे विश्व में बिकता है। डायमंड इंडस्ट्री के जो कारीगर हैं, उनको अंदाजे से 25000 रुपये से ज्यादा पगार मिलती है और उनको यदि प्रशिक्षित किया जाए तो उत्पादन में भी बढ़ावा हो सकता है और इसकी वजह से फॉरेन एक्सचेंज में भी बढ़ोतरी हो सकती है। सूरत शहर के एक डायमंड व्यापारी ने दो तीन महीने पहले अपने रत्न कलाकारों को, जिन्होंने वैल्यू एडीशन दिया, जिन्होंने अच्छा प्रोडक्शन दिया, उन लोगों के लिए अलग अलग कैटेगरी में इनाम दिया, किसी को कार दी, किसी को फ्लैट दिया, किसी को डायमंड की ज्वैलरी दी तो एक तरह से उनको प्रोत्साहित करने की कोशिश की क्योंकि उसको फायदा हुआ था। 450 कारें उनको अपने कारीगरों को दी थीं। बाकी मकान वगैरह तो अलग से है।

मुझे लगता है कि विशेष रूप से गुजरात में ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री को बढ़ावा दिया जा रहा है। बड़ी बड़ी ऑटोमोबाइल कंपनियां आज गुजरात में हैं। गुजरात ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री की वजह से भी जाना जाता है और आज जो उत्पादन शुरु किया है तो उनको भी स्किल्ड वर्कर्स की आवश्यकता है। इसलिए उनके लिए भी ट्रेनिंग सेंटर्स खोले जाने चाहिए। आज के जमाने में हाउस कीपिंग भी बहुत बड़ी इंडस्ट्री बनने जा रही है। हमारे राष्ट्रपति भवन से लेकर बड़ी बड़ी इमारतों में भी हाउस कीपिंग का कांट्रैक्ट दिया जाता है। उनके लिए भी स्कूल वर्कर्स की आवश्यकता होती है। हमारे देश में कृषि क्षेत्र ही सबसे ज्यादा रोजगार लोगों को देता है। मगर वहां भी कृषि वर्कर्स के लिए कोई ट्रेनिंग की व्यवस्था नहीं है लेकिन अनस्किल्ड होने के बावजूद भी अपने अनुभव के आधार पर कृषि क्षेत्र के वर्कर्स ने उत्पादन में क्रांति की है और जरुरत से ज्यादा धान का उत्पादन उन्होंने बढ़ाया है। हम कृषि उत्पादन में स्वावलंबी बने हैं और अगर उनके लिए सैमीनार द्वारा छोटे छोटे वर्कशॉप करके उनको ट्रेन्ड किया जाए तो उससे ज्यादा उत्पादन होने की संभावना है। इससे देश की आर्थिक व्यवस्था में भी मजबूती आ सकती है। मेरी जानकारी के मुताबिक भारत सरकार ने वर्ष 2022 तक 50 करोड़ लोगों को स्किल डवलपमेंट देने का लक्ष्य रखा है और माननीय प्रधान मंत्री जी ने उस लक्ष्य को पूरा करने के लिए ही इस दिशा में अपने कदम बढ़ाए हैं। लक्ष्य के प्रति उनकी गंभीरता हम देख रहे हैं और वर्ष 2022 तक इस लक्ष्य को वह जरूर पूरा कर सकते हैं।

भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों और राज्य सरकारों को अपनी अपनी योजनाओं के द्वारा स्किल डवलपमेंट आगे बढ़ाने की जिम्मेदारी दी गई है। अभी जो स्किल डवलपमेंट का कार्य हो रहा है, उस कार्य में तेजी लाने के लिए मेरे कुछ सुझाव इस प्रकार हैं कि भिन्न भिन्न मंत्रालयों और राज्यों द्वारा कौशल्य विकास के लिए अपनी अपनी योजनाएं चलाई जा रही हैं। उनके बदले में उन सबको एक साथ जोड़ने की जरूरत है। यानी पूरे राष्ट्र के लिए कौशल्य विकास के नॉर्म्स और पाठ्यक्रम को एक जैसा करने की आवश्यकता है। कौशल्य विकास के नॉर्म्स और पाठ्यक्रम पूरे देश में एक करने के बाद इससे संबंधित मंत्रालय और विभाग जिस लक्ष्य पर काम कर रहे हैं, उसकी प्राप्ति के लिए विशेष मॉनिटरिंग की आवश्यकता है, लक्ष्यों के सम्पूर्ण प्राप्ति में कोई कमी न रहे। कौशल विकास से संबंधित वर्ष 2022 के लक्ष्य को पूरा करने के लिए स्किल कोर्स को दो भागों में बांटने की आवश्यकता है। एक है, जो युवक और युवतियाँ पहली बार मार्केट में आ रहे हैं, उनके स्किल डेवलपमेंट का कोर्स अलग होना चाहिए क्योंकि वे इस क्षेत्र में नये हैं और जो पहले से ही काम कर रहे हैं, उनको रि-स्किलिंग करने की आवश्यकता है क्योंकि उनके पास जो कौशल्य है, वह पूर्ण नहीं है। उनको पूर्ण कौशल्य देने के लिए उनकी प्रोडक्टिविटी और एफिसिएंसी बढ़ाने के लिए उनका कोर्स अलग प्रकार का होना चाहिए। स्कूलों में सेकेन्ड्री और हायर सेकेन्ड्री लेवल पर वोकेशनल ट्रेनिंग सेन्टर का एक विषय जोड़ने की आवश्यकता है। उससे आत्मनिर्भरता बढ़ती है और हमारा लक्ष्य जल्दी पूरा हो सकता है। अभी जो स्किल दी जा रही है उसका एक सर्टिफिकेशन होना चाहिए।

माननीय प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था कि स्किल्ड वर्कर को हम एक्सपोर्ट भी कर सकते हैं। इसलिए स्किल देने के बाद सर्टिफिकेट बहुत जरूरी है। इसे देने के लिए भारत में सर्टिफाइड एजेंसी की जरूरत भी होगी। केवल सर्टिफिकेट आधार पर उसको अलग-अलग देशों में जाने में सुविधा हो जाएगी। कौशल्य विकास के लिए मंत्रालय और राज्य सरकार की बहुत सारी संस्थाएं काम कर रही हैं। अब जरूरी यह है कि उनका आउटकम क्या है, यह जानने के लिए इंस्टीट्यूट को यह जिम्मेदारी दी जाए कि स्किल कोर्स करने वाला युवक और युवती कोई बिजनेस कर रहा है या नहीं, किसी फैक्ट्री में काम कर रहा है या नहीं? इन सब जानकारी से हमें पता चलेगा कि हम सही दिशा में जा रहे हैं या नहीं? मेक इन इंडिया प्रोग्राम को सफल बनाने के लिए भारत को एक मजबूत मेनुफेक्चरिंग फाउण्डेशन बनानी होगी। इंजीनियरिंग सेक्टर का कंट्रीब्यूशन पिछले कई वर्षों से 15 प्रतिशत पर ही टिका है। हमारे पास एक ऐसा प्रपोज़ल है कि हम इसे 25 प्रतिशत तक ले जा सकते हैं। मेनुफेक्चरिंग सेक्टर अभी भी लेबर फोर्स का 12.6 प्रतिशत है। मेनुफेक्चरिंग सेक्टर के पास ऐसी क्षमता है कि वह और जॉब पर यूनिक आउटपुट दे सकता है। 25 बिलियन नए काम पैदा करने में इस सेक्टर का बड़ा योगदान है। अभी इसमें और बढ़ोतरी की गुंजाइश है। यह एक ऐसा सेक्टर है जो देश को उन्नति की नई मंजिलों की ओर ले जा सकता है और देश का नाम रोशन कर सकता है। टारगेट को प्राप्त करने के लिए सरकार को मेनुफेक्चरिंग के रास्ते में जो कठिनाइयां आती हैं, उन्हें दूर करना होगा। ऐसा करने से एक ओर मेक इन इंडिया को बढ़ावा मिलेगा, वहीं दूसरी ओर इंजीनियरिंग क्षेत्र में स्किल लोगों को काम भी मिलेगा। हमें हमारे देश के उद्योगों को बढ़ावा देना होगा ताकि उससे ज्यादा से ज्यादा लोगों को काम मिल सके। स्किल को बढ़ावा देने का एक कदम देश में मेनुफेक्चरिंग सेक्टर को मजबूत करना होगा और उसको ऐसा बनाना होगा कि वह अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर भारत को एक पहचान दे सके।

आपने मुझे बोलने का मौका दिया उसके लिए मैं आपका बहुत-बहुत धन्यवाद करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Motion moved:

> "Keeping in view the commitment of the Union Government to promote the development of our country, which can be effectively realized through 'skill development', this House urges upon the Government to frame a comprehensive scheme providing for development of such technical skills amongst youth as would enable them to contribute towards making India a modern country and in achieving the goal of 'Make in India'."

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY (BAHARAMPUR): Sir, in the beginning, I must appreciate the hon. Member and esteemed colleague Shri C.R. Patil who has moved his Resolution which is very much relevant in view of the present situation of our society, in view of the job opportunities in our country, and the growing need for skills.

In this year's Budget, it has been stated that India is one of the youngest nations in the world with more than 54 per cent of the total population below 25 years of age. Our young people have to be both educated and employable for the jobs of the 21st century.

The hon. Prime Minister explained how 'Skill India' has to be closely coordinated with 'Make in India'. Yet, today less than 5 per cent of our potential work force gets formal skill training to be employable and stay employable. In the Economic Survey of 2015 it has been stated that merely 2 per cent of the country's work force is skilled. There is a dual challenge of developing skills and utilising them in a proper way. Promoting growth of micro, small and medium enterprises is critical from the perspective of job creation which has been recognised as a prime mover of the development agenda in India.

Sir, the problem is that there is a dearth of formal vocational education, high school drop-out rates, inadequate skill training capacity, negative perception towards skill, lack of industry-related skills even in professional courses. These are the major causes of poor skill level of India's work force. The Survey said that the major impediment to the pace of quality employment generation in India is the small share of manufacturing in total employment. However, National Survey Organisation's 68th Round indicated a revival in employment growth in manufacturing from 11 per cent in 2009-10 to 12.6 per cent in 2011-12. This is significant given that the National Manufacturing Policy 2011 has set a target of creating 100 million jobs by 2022.

We need skill because there is a severe shortage of skilled manpower in our country. So, in spite of the fact that India is host to the largest youth population in the world, we have so far failed to extract the demographic dividend of our youth population. So, we have to be very careful that in the rhetorical exercise of 'Make in India' or 'Skilled India' and see that our demographic dividend should not get translated into a demographic burden. To that end, the Indian Government has been pursuing, for long, various skill development programmes in our country. When we attained Independence, 80 per cent of our population used to live in the rural areas, it has now been reduced to 70 per cent. When we attained Independence only 12 per cent of our population was educated, now the percentage has been increased to 74 per cent of our population. However, in spite of all the advantages we have gained over the decades, there is a severe mismatch between the supply of skilled manpower and the demand for it. Now, technology has been growing in a mind-boggling pace. Industry needs more and more technology savvy skilled work force which we need in order to cater to promote our economy, in order to create employment opportunities.

To achieve this target, the Skill Development Policy was announced in the year 2009 and a governance structure was designed. A Council with the hon. Prime Minister as the Chairperson was constituted to drive the policy. National Skill Development Corporation was set up in 2011 to involve the private sector in this initiative and a target to train 150 million workers was assigned to them. Budgets and targets were allocated to about 17 Ministries.

16.00 hrs

For better coordination among various stakeholders, a National Skill Development Coordination Board was set up in the year 2008 under the Planning Commission. In order to devise the strategy, chart out the plan, promote skill development, provide guidance to stakeholders and implementing agencies, a National Skill Development Agency under the Ministry of Finance was constituted. The National Skill Development Policy also outlined the academic structure by constituting National Skill Qualification Framework which provides horizontal and vertical entry and exit system in pursuing vocational education. Vocational education is an imperative need to skill our future generation.

What is the present scenario of unemployment in our country? Why do we need Skill India? Why do we need India should be a skilling capital of the world, a skilling hub of the world? It is because India has a great opportunity. In the developed countries like America, Europe and Japan, gay population has been increasing which could be compensated by the talent outflow, by the skill outflow of the Indian population.

Sir, I would like to draw the attention of our hon. Minister Shri Rudy ji who has taken the charge of this very precious Ministry. However, I do not know how he will coordinate with the Ministries concerned so as to converge all the programmes into the skill development domain because it is an intricate job that, I think, he has been entrusted with. However, I am wholeheartedly wishing him a bright success.

SHRI MALLIKARJUN KHARGE (GULBARGA): I just take a minute. Hon. Minister, Shri Chowdhury is praising you a lot. I think he is thinking that you are going to give a lot of money to West Bengal and other areas! But totally your Budget itself is hardly, I think, Rs.40 crore or something like that. It is not much. You have to stretch your hands to all the Departments and collect it.

हमारे यहां एक कहावत है कि - एक रुपए का बजट और घड़ी भर की फुर्सत नहीं, यह विभाग भी वैसा ही है। आप स्किल डवलपमेंट के लिए इतना पूचार कर रहे हैं, उसे देखते हुए और आपके बजट को देखने से लगता है कि इस साल स्किल डवलपमेंट में कुछ होने का अंदाजा नहीं दिखाई दे रहा है। जब तक प्रधान मंत्री जी और वित मंत्री जी आपके साथ नहीं होंगे, तब तक कुछ होने वाला नहीं है।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री राजीव प्रताप रूडी**):** आपकी आखिरी बात का जवाब देना चाहता हूं कि बजट से कम से कम 25 गुना ज्यादा हमारे पास साधन हैं। भारत सरकार में लगभग तमाम मंत्रालयों द्वारा इस पर 6,000 से 7,000 करोड़ रुपए खर्च हो रहे हैं।

HON. CHAIRPERSON : He is a coordinator!

SHRI ADHIR RANJAN CHOWDHURY: Sir, what I would suggest is that the Government has to realize that out of the total training so far provided in skill development which caters to the organized sector, it is providing jobs only to 9 per cent. We need to look towards our unorganized sector and improve the skills of workers so that they benefit from this Mission. We also need to understand the strength of our villages and forests which cater to half of the job opportunity of the country. Unless our farmer improves his skills, he will not be able to produce more.

We have more than 250 non-timber forest products in our forests which can change the life of the tribal and improve his living condition. Only if we skill them and provide them with techniques like processing, packaging, and marketing his products, it would help them to reap the benefits from this programme.

What is the present scenario? Sir, 2011 data found that more than 20 per cent of Indians in the age group of 15-24 years were jobless and are still seeking work. In absolute terms, this army of unemployed is staggering huge around 4.7 crore, of which 2.6 crore were man and 2.1 crore were women. Among Dalits, the unemployment rate in the working age population of 15-59 years was a shocking 18 per cent, which is much higher than the general population. Among Adivasis, the unemployment rate was even higher, over 19 per cent. These are the two most marginalised sections of Indian society, and clearly they are struggling with widespread unemployment.

Naturally, those sections need to be given prime focus so that we can create an inclusive society. To that end, the National Manufacturing Policy of the Government was framed for providing 10 crore jobs by the year 2012. According to the last three surveys, the workforce grew from 45.91 crore persons in 2004-05 to 47.41 crore persons in 2011-12; the unemployment level decreased from 1.08 crore to 1.06 crore during the corresponding period. In order to improve the employability of the youth, around 20 Ministries run skill development schemes across 70 sectors.

What is the National Skill Development Mission? The National Skill Development Mission was launched in 2010 which consists of three institutions – the National Council of Skill Development, the National Skill Development Coordination Board, and the National Skill Development Corporation. The National Policy on Skill Development was approved by the Indian Government. The target sometime fixed for the financial year 2011-12, skilling target was fixed at 46.53 lakhs, and the achievement was 45.58 lakhs, that is, 98 per cent. In 2012-13, 72.51 lakh target was fixed and the achievement was 72 per cent. For 2013-14, 73 lakh skilling target was fixed, and the achievement was 104 per cent. For 2014-15, skilling target was fixed at 105 per cent was fixed but the achievement was 31.5 per cent.

I know that I do not have adequate time as is required. What I would like to draw the attention of the Government is that while devising the New Development Scheme, the Government should take a meticulous planning, and create a proper futuristic scenario so that the chasm between the skill gaps could be bridged. The skill gaps and the potential job opportunities should be linked while formulating any skill development scheme.

Skill development programmes should be focused on creating self-employment needs, to have adequate market linkages, such as, access to marketing know-how, coordination between sellers and buyers, low-cost financing that will help the newly skilled entrepreneurs to stay afloat and grow.

Sir, the newly skilled entrepreneurs could provide a huge potentiality especially to the unemployment sectors in our backward regions. Ruralization is another aspect that needs to be taken care of. During the period from 2004-05 to 2011-12, about 37 million people left agriculture and strived hard to earn from the urban areas. So, there had been a huge exodus that took place during that period. But already our urban infrastructure is about to crumble. Our urban infrastructure is not adequate to cope up the huge inflow, the huge migration, the huge traffic from rural to urban area. That is why, we should devise our ways and means so that rural unemployed youths could be better accommodated in entrepreneurial jobs, in skilled jobs in their own environment so that the migration from rural to urban area could at least be abated.

Secondly, it is a very pertinent issue that मान लीजिए मैंने किसी को स्किल्ड बना दिया, स्किल्ड बनाने के बाद क्या होगा। पहले हमें यह देखना पड़ेगा कि स्किल करने के बाद उन्हें

नौकरी मिले। दूसरा यह देखना पड़ेगा कि उनकी नौकरी की गारंटी रहे। उनकी सिक्युरिटी क्या होगी, उनका अपग्रेडेशन क्या होगा, ये सारी चीजें हम सबको देखनी पड़ेंगी। सिर्फ स्किल्ड बनाना ही हमारे काम का अंत नहीं है। स्किल बनाने के बाद उसके साथ और जो दूसरे मुद्दे हैं, उन सबके ऊपर हमें विचार करना चाहिए। हमारे देश में हम लोग टैक्नोलोजी के क्षेत्र में काफी आगे बढ़ चुके हैं। हाउस में मंत्री जी बोलते रहते हैं कि 97 परसैन्ट पापुलेशन को मोबाइल सुविधाएं उपलब्ध हो रही हैं।

Technology can be considered a harbinger of such a change and inclusive skills development. However, poor internet connectivity still remains a bugbear. Internet connectivity needs to be enhanced because we have a programme of National Optical Fibre Network which is amounting to Rs. 20,000 crore and which aims to provide high-speed broadband connectivity to 2,50,000 gram panchayats across the country in order to deliver services such as healthcare, education and commerce. My question is this. Why cannot this be utilized to deliver skills training in Government school premises that lie unused after school hours? स्कूल खत्म होने के बाद इन स्कूलों के सारे एरियाज को हम लोग स्किल डैवलपमैन्ट के लिए इस्तेमाल कर सकते हैं, क्योंकि जो स्किल डैवलपमैन्ट चाहते हैं, उन्हें दस से पांच स्कूल की जरूरत नहीं होती है। मुझे यह कहने में अफसोस होता है कि चाहे केन्द्र की सरकार हो या सूबे की सरकार हो, दोनों तरफ से स्किल डैवलपमैन्ट पर ज्यादा से ज्यादा इनवैस्टमैन्ट नहीं हो रहा है। The State Governments and the Central Government, both the Governments should increase allocation towards skill development. जैसे कि सर्व शिक्षा अभियान में, उच्च शिक्षा अभियान में हम पैसे का एलोकेशन कर रहे हैं, उसी तरह स्किल डैवलपमैन्ट में भी हमें पैसे का एलोकेशन करना चाहिए और जो स्कूल्स हैं, इन स्कूलों के करिकुलम में हमें स्किल डैवलपमैन्ट को शामिल करना चाहिए। इसके साथ-साथ ही जो इंडस्ट्रीज हैं, इन इंडस्ट्रीज को हमें परसुएड करना चाहिए कि आप दो-चार स्कूलों को एडाप्ट करो और इन्हें स्किल्ड बनाओ और जॉब अपार्चुनिटी को निश्चित करो। जो इंडस्ट्रीज है, वह जो स्कूल एडॉप्ट करेगा, ये स्किल डिवेल्पमेंट देगी, उन सबको इंसेंटिवाइज करना चाहिए। मैं समझता हूँ कि आने वाले दिनों में स्किल डिवेल्पमेंट के दौरान हमारे देश के जो अनएंप्लॉएड यूथ है, उनके लिए बड़ी सुविधा उपलब्ध होगी। यह कहते हुए मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ।

श्री रत्न लाल कटारिया (अम्बाला) : उपाध्यक्ष जी, आदरणीय पाटिल जी एक बहुत ही महत्वपूर्ण प्राइवेट मैंबर्स बिल ले कर आए हैं, मैं इनके समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूँ। आज हिंदुस्तान को हर साल दो करोड़ स्किल्ड लेबर की आवश्यकता है। जबकि 67 साल की आजादी के पश्चात् हम केवल 43 लाख स्किल्ड लेबर को ही हम ट्रेनिंग दे पा रहे थे। महोदय, अभी खड़गे जी ने खड़ा हो कर हमारे इस जो मिशन के बारे में कहा, जो मिशन हमने स्किल डिवेल्पमेंट का लिया है और जिसके अंतर्गत 2022 तक 50 करोड़ स्किल डिवेल्पमेंट वर्कफोर्स खड़ा करने का संकल्प लिया है। मैं खड़गे जी को यह बताना चाहता हूँ कि 67 साल की आजादी के बाद भी आज तक भारत दुनिया की मात्र 10 प्रतिशत स्किल्ड वर्कफोर्स ही क्यों खड़ी कर पाया? आज कोरिया की जनता का 96 प्रतिशत स्किल्ड है। जापान में 80 प्रतिशत है। जर्मनी में 75 प्रतिशत है। यूनाइटिड किंगडम में 68 प्रतिशत है तो भारत पिछले 67 वर्षों में स्किल डिवेल्पमेंट के मामले में इतना क्यों पिछड़ गया? हिंदुस्तान के अंदर अधिकतर कांग्रेस पार्टी का राज रहा है। ये गरीबों की बात करते रहे, लेकिन इन्होंने हिंदुस्तान के उन 25 प्रतिशत शिडयुल्ड कास्ट और शिडयुल्ड ट्राइब की तरफ भी नहीं देखा, जिनके बच्चे आज विस्फोटक बेरोजगारी का शिकार हैं। आज हिंदुस्तान के अंदर पिछले 67 वर्षों में 10 करोड़ पढ़े-लिखों की फौज खड़ी हो गई, इसका जिम्मेवार आज कौन है? आज भी जब हम देखते हैं कि हमारे यहां इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र के अंदर 10 करोड़ 30 लाख स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है। ऑटोमोबाइल क्षेत्र के अंदर 3 करोड़ 50 लाख लोगों की आवश्यकता है। कंस्ट्रक्शन के अंदर आज भी हमें 3 करोड़ 30 लाख स्किल्ड वर्कफोर्स की आवश्यकता है। ट्रांस्पोर्ट में हमें 1 करोड़ 77 लाख की आवश्यकता है। रिटेल में हमें एक करोड़ 73 लाख की आवश्यकता है। हैल्थकेयर के अंदर आज हमें 1 करोड़ 27 लाख की वर्कफोर्स की आवश्यकता है। जैसाकि मैंने कहा कि हमें हर वर्ष 2 करोड़ स्किल्ड लोगों की आवश्यकता है, हम बधाई देना चाहते हैं भारत के प्रधान मंत्री जी आदरणीय नरेंद्र मोदी जी को, जिनका ध्यान स्किल डिवेल्पमेंट की ओर गया और उन्होंने इसके लिए एक एक अलग मंत्रालय बनाया और मंत्रालय बना कर उसका प्रभार भी एक यंग टर्क मंत्री रूडी जी को दिया है। मैं यह आशा करता हूँ कि जिस प्रकार से ये जहाज को आसमान की बुलंदियों पर ले जाते है, इसी तरह से ये स्किल्ड डिवेल्पमेंट के इस कार्यक्रम को, भारत के इस कार्यक्रम को जो परम आरणीय मोदी जी ने जो शुरू किया है, इस कार्यक्रम को भी ये ऊंचाइयों तक ले जाएंगे।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: वह सब तो अच्छा है, लेकिन हाथ में बैट ही नहीं है तो क्या मारेंगे? ...(व्यवधान)

श्री रत्न लाल कटारिया: बैट है सर। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष महोदय, हमें जो जनसमर्थन मिला है, इस जनसमर्थन में हिन्दुस्तान के युवाओं का बहुत बड़ा योगदान है। हिन्दुस्तान के युवाओं ने आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी की आँखों में एक सपना देखा कि यह वह व्यक्तित्व है जो हमारी एस्पिरेशंस को पूरा कर सकता है। आज यूपीए शासनकाल में भ्रष्टाचार की वजह से, जिस वजह की निराशा हिन्दुस्तान के लोगों के अंदर थी, जिस प्रकार वे अपने भविष्य को लेकर तड़प रहे थे, उनको किसी ऐसे व्यक्तित्व की ज़रूरत थी जो उनको रोशनी दिखा सके। आदरणीय नरेन्द्र मोदी जी ने हिन्दुस्तान के युवाओं को वह रोशनी दिखाई और आज जब हमारी सरकार है, तो उनके सपनों को पूरा करने का सारा दायित्व हमारे ऊपर है। हमारे देश के 25 साल से कम के जो 54 प्रतिशत युवा हैं, ये कल हमारी ग्रोथ स्टोरी को लिखने वाले हैं। आज हमें उस क्षेत्र के अंदर आगे कदम बढ़ाने की ज़रूरत है।

महोदय, आज दुनिया हमारी ओर देख रही है। अभी वर्ल्ड बैंक की चीफ भारतवर्ष आई थीं। उन्होंने कहा कि जो कल तक यह मानते थे कि हिन्दुस्तान कहीं स्टैन्ड नहीं करता, आज वर्ल्ड बैंक की चीफ ने भी यह कहा है कि ऐ भारत के लोगो! सीज़ द अपॉर्चुनिटी। आज दुनिया आपकी ओर देख रही है। आपने नौ महीने के अंदर ही चाइना की अर्थव्यवस्था को भी पीछे पछाड़ दिया है। आज मैं देख रहा था कि भारत के प्रधान मंत्री नरेन्द्र मोदी ने चीन के राष्ट्रपति की लोकप्रियता को भी पीछे पछाड़ दिया है, इस प्रकार के कार्यक्रम हमने अपने देश के अंदर लिये हैं।

मैं आदरणीय सदस्य महोदय का समर्थन करते हुए माननीय मंत्री रूडी जी से पूरी-पूरी आशा करते हुए यह जताना चाहूँगा कि आप भी यंग्स्टर हैं और हिन्दुस्तान का युवा आपके अंदर अपनी आशाओं को पूरा होने का सपना देख रहा है। आइए, हम सब मिलकर इस भारत को महान बनाएँ।

DR. MAMTAZ SANGHAMITA (BARDHMAN DURGAPUR): Respected Deputy-Speaker, Sir, I am very much thankful to you for giving me this opportunity to speak on this Resolution.

First of all, I would like to thank Mr. C.R. Patil for raising this important issue. We can know from the narrations of our colleagues that it is a very important issue regarding 'Make in India' as it is related to skill development. About 65 per cent population of India is youth and most of them are without any job.

We are glad that we are having so much of youth, which should be the main workforce for building modern India. But it is for our policies, programmes and initiatives that we could not make use of them.

The previous speaker from West Bengal has already said about the steps of coming to this position of idea of skill development. Though it is coming in phases in different ages – from year after year – yet there is no comprehensive programme really to deal with that. अगर यह रिजॉल्यूशन साकार हो गया तो यह काम में आएगा। Most of the people have said what is it about, what we should do but I think it has got various stages. First of all, 'Make in India' vision is a very good thing and to make that vision it in action requires proper planning. In this resolution, we have a big task because it involves

actually a holistic approach by different Ministries and different sorts of people. So, everybody has said so and has given various statistics also. I would just mention a few things to be included, if possible, in this Skill Development. There are a lot of workers who are unskilled who make the gold ornaments. The main force of making ornaments for different parts of our country especially for the Gujarat and Mumbai people are from the West Bengal especially from the areas of Murshidabad, parts of Nadia district, Howrah, Burdman and Hooghly. These people are quite efficient and they are doing the job at various places but because of their non-availability of the recognized certificate/degree, they are really very ill-fed. If we can put them under Skill Development Programme and give a proper certification, they can have their own small enterprises. They are also going to Middle East and other foreign countries but they hardly are paid. There they can have foreign money also for India if they are also properly skilled.

There is another section of workers who are lady zari workers. I do not know about the other States. Zari work is done all over India. Adhir Choudhary who is my friend, always mentions about zari workers. He is from Murshidabad. Most people of Murshidabad and Howrah belt, work in the zari field. He mentioned about the provision of the Skill Development programmes through rural regions. I request that zari workers also need a proper skill and zari work is done in saree and dress materials. It is very popular not only all over India and the sub-continent but also these things are transported to the other places, that is to the developed countries.

We also have another section of workers who are very innocent. They are very skilled but they do not have any certification. They are mason workers. We call them *Raj Mistries* who make the building and they are very good in architecture. If you can visit the villages in the Bengal, you will be very surprised to see very beautiful small buildings with good architectural beauties and those *Raj mistries* are not even trained. If we make the provision of this skill development, it will be very good. These Raj mistries are building big mansions in UK and even in France. They are constructing the bridges with the help of these workers.

There is another one. You know, it is West Bengal's beauty stitches, that is, *katha's* stitch over the rugged clothes. It is made for ओढ़ने वाले चद्दर के लिए होते हैं। Now it is used in sarees and dresses all over. The other day we had a meeting with the European Parliamentarians. There, one of the ladies wore something like *katha* cloth. She asked me, "What is this?" I said, "This is a stitching system, and it is coming from West Bengal." So, this is very popular. So, those unskilled workers can be taken under the purview and we can teach many other people in these things also.

Another thing that we all know is garment business. I am sorry. I do not remember the name of my friend. From Gujarat somebody has already mentioned about the clothes and other things in Surat. I would say now-a-days, whenever we go to UK, USA or anywhere, when you buy a shirt in big shops in the markets like Spencer and all, you will find either it is made in China or Korea or Bangladesh, and the fifth country is India. So, we can become first also in this stitching and tailoring business.

Another fact is that the women of Bangladesh are empowered by the Government. So, we can make the same thing in India suiting to our purview also because as you know about the garment factories in Bangladesh, they are all run by women.

Then, you may know another thing which is leather design. The Shanti Niketan leather design is famous. This also needs skill development. Those Shanti Niketan bags, shoes, etc., are famous. So, with this skill development, we can empower the youth. They can be imparted skill training. As already Adhir Chowdhury said, not only in micro enterprises but also in bigger enterprises and even in factory produced things, we can impart them skill training.

As far as including this in schools is concerned, my other friend has suggested for including it in school. That may be possible. Or, even if it is not possible, we can do these things with the school dropouts. Along with some teachings in mathematics or in vernacular language and a little bit of English, we can give them certification. Later on, I would request our hon. lady Minister in the HRD Ministry regarding this.

It is a very pertinent Resolution. I think we should all pass it. The constraint of the Minister is money. Everybody knows that. As you have already mentioned, that money may be coming. I should say it is a holistic approach. If it is concerned with women empowerment, then the Department of Women and Child Development can give some of it or we can give it by loan also to the skill developed persons so that when they make enterprise, they can return part of it back to the Government.

With these few words, I am concluding. Thank you very much.

डॉ. मनोज राजोरिया (करौली-धौलपुर): उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे श्री सी.आर. पाटिल जी "मेक इन इंडिया" और स्किल इंडिया के ऊपर प्राइवेट मैम्बर रेजोल्यूशन लेकर आए हैं, उस पर मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूं।

देश में जब भी कोई बच्चा स्कूल जाता है तो वह एक सपना लेकर जाता है कि मैं पढ़ूंगा-लिखूंगा, और अपने पैरों पर खड़ा होऊंगा। उसका पूरा परिवार और वह 25 साल तक इस उम्मीद में शिक्षा प्राप्त करते हैं कि बच्चा बड़ा होकर आत्मनिर्भर बनेगा और कुछ रोजगार पाएगा और अपने पैरों पर खड़ा होगा। यह दुर्भाग्य है कि हमारे देश में जो शिक्षा प्रणाली थी, जिस तरह से बच्चे पढ़ कर निकलते थे, वे किताबी पढ़ाई तो करते थे, लेकिन योग्यता में कहीं न कहीं कोई ऐसी कमी रह जाती थी, जो योग्यता उन फैक्ट्रीज, कंपनियों और बड़े-बड़े लोगों को चाहिए थी, उनमें वह फिट नहीं होती थी। इसी वजह से हमारा युवा, हमारा व्यक्ति जो मेहनत करता था, लम्बी मेहनत के बावजूद भी कहीं रोजगार प्राप्त करने से दूर रह जाता था। आदरणीय प्रधान मंत्री जी ने इस पीड़ा को बहुत गहराई से समझा था। एक बार उन्होंने लाल किले से भी सुनाया था कि उनके पास एक लड़का आया तो उन्होंने पूछा कि क्या करते हो। वह बच्चा नौकरी चाहता था। उसने कहा कि बीए पास हूं। दुबारा पूछा कि तुमको क्या आता है। उसने फिर बोला कि बीए पास हूं। तब प्रधान मंत्री जी को भी लगा कि लोग शैक्षणिक योग्यता और किताबी ज्ञान को ही अपनी योग्यता समझ लेते हैं। प्रधान मंत्री जी ने इस कमी को बहुत गहराई से समझा था। जब पहली बार लाल किले से उन्होंने भाषण दिया, उसी में उन्होंने अपनी पीड़ा को उजागर किया था। उन्होंने उसी भाषण में संकल्प लिया था कि इस देश में हम स्किल इंडिया डैवलपमैंट का एक ऐसा कार्यक्रम तैयार करेंगे जो देश को आत्मनिर्भर बनाने के लिए, पूरी दुनिया में सम्मान दिलाने के लिए मेक इन इंडिया का सपना भी पूरा करेंगी। प्रधान मंत्री जी ने इसी सपने को पूरा करने के लिए लाल किले से घोषणा की थी। लाल किले से घोषणा नेशनल स्किल डैवलपमैंट एजेंसी के माध्यम से प्रधान मंत्री जी ने 13 जून, 2014 में अपनी प्रतिबद्धता को, जो देश के युवाओं, बेरोजगार लोगों के लिए थी, उसे दर्शाया था। इसे पूर्ण करने के लिए हमारे होनहार मंत्री श्री राजीव प्रताप रूडी को कार्य दिया गया। उन्होंने लगभग 22 मंत्रालयों और अन्य विभागों के साथ मिलकर 73 प्रकार के ऐसे कोर्सेज डिजाइन किए जिसके माध्यम से डैवलपमैंट स्कीम का लाभ दे सकें। देश के हर जिले में स्किल डैवलपमैंट का कोर्स चलाकर उसका लाभ उन युवाओं को

रोजगार देने के लिए कर सकें, ऐसा समन्वय, योजना युवा मंत्री द्वारा बनाई गई। मुझे उम्मीद है कि इस योजना का लाभ पूरे देश में वे सभी सांसदों के साथ मिलकर पूर्ण करेंगे।

प्रधान मंत्री जी ने देश के लोगों के लिए वर्ष 2022 तक कुछ लक्ष्य रखे हैं। उनमें महत्वपूर्ण लक्ष्य यह है कि 2022 तक लगभग 30 करोड़ लोगों को स्किल डैवलपमैंट के माध्यम से ट्रेनिंग देकर अपने पैरों पर खड़ा किया जाए, उन्हें आत्मनिर्भर बनाया जाए। मैं आशा करता हूं कि सभी सांसद, पूरी टीम इंडिया मिलकर इस महत्वपूर्ण लक्ष्य को उनके साथ कंधे से कंधा मिलाकर खड़ा करेंगे।

क्रिसल नाम की एजेंसी ने एक सर्वे किया कि वर्ष 2005 से 2010 के बीच लगभग 10 करोड़ युवाओं ने श्रम बाजार में प्रवेश किया था। वे इस लैवल पर आए कि श्रम शक्ति के माध्यम से रोजगार पा सकते थे और देश के निर्माण में साथ दे सकते थे। यह बहुत दुर्भाग्य का विषय रहा कि इन 10 करोड़ श्रम शक्ति का उपयोग न के बराबर हुआ और इनमें से सिर्फ 5 प्रतिशत युवाओं को रोजगार देने में हम सफल रहे। उस वक्त क्या कमियां रहीं, उन्हीं को ध्यान में रखकर प्रधान मंत्री जी ने स्किल इंडिया डैवलपमैंट को मिशन बनाया। देश के युवाओं को आत्मनिर्भर बनाने के साथ देश का गौरव बढ़ाने, हर चीज का उत्पादन देश में करने के लिए उन्होंने मेक इन इंडिया का एक सपना देखा था। मेक इन इंडिया के सपने की उन्होंने 25 सितम्बर, 2014 को पूरी दुनिया के सामने विज्ञान भवन, नई दिल्ली में घोषणा की। उसी दिन से पूरी दुनिया की नजर भारत पर लगी थी। मैं आशा करता हूं कि प्रधान मंत्री ने पूरी दुनिया के देशों को आह्वान किया था कि हिन्दुस्तान आइए और भारत में इन्वैस्टमैंट कीजिए, एफडीआई की योजना बनाकर विभिन्न देशों को निमंत्रण दिया था। फॉरेन डायरैक्ट इन्वैस्टमैंट न होकर फर्स्ट डैवलप इंडिया उनका मिशन बन गया था।

मैं राजस्थान सरकार की स्किल इंडिया डैवलपमैंट की योजना की इसके अंतर्गत तारीफ करना चाहूंगा। राजस्थान की मुख्य मंत्री श्रीमती वसुंधरा राजे ने प्रधान मंत्री जी की इस भावना को देश में सबसे पहले हाथों-हाथ लिया था।

मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि राजस्थान देश का पहला राज्य है, देश के अंदर सबसे ज्यादा स्कील डेवलपमेंट में अगर किसी ने कार्य किया है तो वह श्रीमती वसुंधरा राजे जी के नेतृत्व में भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने राजस्थान में किया है। मै विश्वास कर सकता हूं कि हमारे मंत्री जी, प्रधानमंत्री जी और हमारी सरकार मिलकर स्कील इंडिया और मेक इन इंडिया के माध्यम से हमारे देश के युवाओं, देश के नौजवानों को रोजगार और योग्यता के अनुसार उनको रोजगार देगी, आत्मनिर्भर बनाएगी और मेक इन इंडिया के माध्यम से प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में भारत देश में नहीं पूरी दुनिया में अपना नाम रौशन करेगा और हर व्यक्ति आत्मनिर्भर और सम्मान से जीने का हक पाएगा।

श्री एस.एस.अहलुवालिया **(दार्जिलिंग):** महोदय, हमारे विद्वान साथी सी.आर.पाटील जी द्वारा पेश किए गए प्रस्ताव का समर्थन करने के लिए खड़ा हुआ हूं। हमारे देश की संरचना गांव की संरचना है। पूरा देश गांव में बसता है, जब उसकी परिकल्पना बनाई जाती है वहां के किसानों को एक नाई की जरूरत पड़ती थी, एक धोबी की जरूरत पड़ती थी, एक वैद्य की जरूरत पड़ती थी, एक दाई की जरूरत पड़ती थी। किसान के साथ पशुपालक, लोहार और कुम्हार और बढ़ई की जरूरत पड़ती थी और इनके पास अगर कौशल नहीं होता तो इनकी जरूरत नहीं पड़ती। यह कौशल उनको प्रकृति प्रदत्त या परिवार प्रदत्त था। यही कारण है कि जब हम गांव में जाते हैं तो लोग पूछते और कहते हैं कि क्या किसान का बेटा किसान ही बनेगा, क्या कुम्हार का बेटा कुम्हार ही बनेगा, लोहार का बेटा लोहार ही बनेगा, बढ़ई का बेटा बढ़ई ही बनेगा, सोनार का बेटा सोनार ही बनेगा और कलेक्टर का बैटा कलेक्टर ही बनेगा, क्या ऐसा होगा? इस समाज के परिवर्तन के लिए ही सारा कुछ हुआ। माननीय प्रधानमंत्री जी का कौशल विद्या की तरफ आकर्षित होना, उसका भी यही कारण है। कालांतर में हमने देखा है कि कभी भारत कौशल विद्या में सबसे अग्रिम था, उसका प्रतीक है, उसका साक्षात उदाहरण है, आज भी बड़े बड़े वैज्ञानिक नहीं बता सके हैं कि अशोक स्तंभ जो लगा हुआ है वह किस ऐलाए का बना हुआ है और उस ऐलाए को गलाने के लिए कौन सी भट्टी यूज की गई थी, वह कितनी बड़ी भट्टी थी, कितनी बड़ी ब्लास्ट फर्निश थी या कास्टिंग फर्निश थी, वह तकनीक किसके पास थी, उसे कौन लेकर आया था, आज तक उसका जवाब नहीं दे सके हैं। यही नहीं मुगलिया सल्तनत के समय जो ताजमहल बना, उसको बनाने वाले कारीगर कौन थे? उसे बनाने वाले कारीगर भारतवासी ही थे। अगर कौशल विद्या नहीं होती तो ताजमहल नहीं बन पाता। जो बिना बीम लगाए हुए स्तूप बने हैं, बौद्ध धर्म के जितने भी स्तूप बिना कोई बीम दिए हुए बने हैं, बिना कोई रिइनफोर्समेंट दिए हुए बने हैं, यह टेक्नोलॉजी कहां से आई, यह वास्तुकला कहां से आई, यह वास्तुशास्त्र किसका है, वह कौन सी टेक्नोलॉजी थी। आप पूरे दक्षिण भारत के मंदिर देख लीजिए, पश्चिम भारत और राजस्थान के किले देख लीजिए, मंदिर देख लीजिए, इन सारी चीजों को अगर आप देखेंगे तो इनको देखने के बाद आपको पता चलेगा कि सारे कारीगर भारतवासी ही थे, हमारे ही पूर्वज थे। पार्लियामेंट को बनाने का निर्णय ब्रिटिश साम्राज्यवाद ने लिया हो लेन इसे बनाने वाले कारीगर यहीं के थे, आर्किटेक्ट का नक्शा बनाने वाला बाहर से आया होगा, आज नक्शे यहां बनते हैं और विदेशों में जाते हैं।

महोदय, मलमल का पूरा थान एक अंगूठी के बीच में से पार कर दिया जाता था, यानी इतनी महीन मलमल बनाने वाले लोग भी यहां थे। यह हाथ के करघे से बनती थी और जहां पर सूत काता जाता था। यह कौशल विद्या थी। यह कौशल विद्या किसी गुरूकुल में पढ़ाई जाती थी, किसी विश्वविद्यालय में पढ़ाई जाती थी। वह कहां विलोप हो गयी? वह कौशल विद्या युग-युगान्तर, यानी प्रकृति से लेकर परिवार में आयी और परिवार से उसका ट्रांसफर, हस्तांतरण होता रहा। किन्तु इस कौशल विद्या में जो अर्निंग है, वह कम होती गयी। जब ट्रेड एंड कामर्स का जमाना आया, तो लोग दूसरी तरफ जाने लगे। लोगों ने हाथों के औजारों पर विश्वास करना छोड़ा और मशीन पर विश्वास करना ज्यादा शुरू किया।

महोदय, यही कारण है कि जब कहीं ब्रिटिश साम्राज्यवाद का सूरज कहीं नहीं डूबता था, तो उस समय सारी दुनिया में जितने भी काम होते थे, वे ब्रिटिश स्टैंडर्ड के तरीके से होते थे। अमेरिका के आजाद होने से पहले जर्मनी ने अपने स्टैंडर्ड लगाये। लेकिन अमेरिका ने आजाद होने के बाद अमेरिकी स्टैंडर्ड लगाये। यही कारण है कि हमारे यहां जहां-जहां ब्रिटिश साम्राज्य रहा, वहां-वहां राइट हैंड ड्राइव है। राइट हैंड ड्राइव की गाड़ी मिलती है। किन्तु जहां-जहां ब्रिटिश साम्राज्यवाद नहीं था, वहां-वहां लैफ्ट हैंड ड्राइव की गाड़ी मिलती है। वहां ट्रैफिक उलटा चलता है। उसके पीछे भी टेक्नोलॉजी है, एक सोच है। लेकिन मेरा कहना है कि इन सारी चीजों में हम कहां पिछड़ गये? हमसे पहले जापान बहुत आगे निकल गया, जर्मनी निकला, फिर चीन निकला। उसका कारण क्या है? जर्मनी क्यों आगे निकला? आज भी अगर संस्कृत का कोई विख्यात, विद्वान, प्रकांड पंडित है, तो वह भारतवासी न होकर एक जर्मन है। वह क्यों है? उसका कारण यह है कि हमारी पाण्डुलिपियां जो उस भाषा में लिखी हुई थीं, वे सारी की सारी उठाकर ले गये और उन्होंने उसका अनुवाद किया। जो हमारा मास्टर कम्प्यूटर है, जिसे लेकर हम इतना गर्व करते हैं और अमेरिका से इम्पोर्ट करके हिन्दुस्तान लाते हैं, वह मास्टर कम्प्यूटर कहां लिखा हुआ है? उसका बनाना हमारी ही पाण्डुलिपियों में लिखा हुआ है।

यह आर्यभट्ट का देश, जिसने जीरो का कान्सैप्ट दिया, जिसने सारी दुनिया को थर्टीन फार्मूला ऑफ एलजेबरा दिया, उस देश से तकनीकी बाहर चली गयी, कौशल बाहर चला गया। आज हम कौशल बाहर से लाने की कोशिश करते हैं। हम अपने आपको जागृत करने की कोशिश कर रहे हैं। हमने नैशनल डेवलपमैंट, स्किल डेवलपमैंट काउंसिल बनाया है। मुझे आश्चर्य है कि हमारी दूरदर्शिता कहां अटक गयी है? हम अटक गये कि रियल एस्टेट में कितने लोग लगेंगे, उसके बारे में सोचिए। इंडस्ट्री में कितने लोग लगेंगे, उसके बारे में सोचिए। हमने अभी तक उसका इन्वयूवेशन सिर्फ थर्टीन सैक्टर्स में किया है।

महोदय, मैं आपको बताना चाहता हूं कि सबसे ज्यादा सब्जैक्ट वाइस ट्रेड को इन्वयूवेशन आस्ट्रेलिया ने किया है। आस्ट्रेलिया की आस्ट्रेलियन वर्कफोर्स एंड प्रोडेक्टिविटी एजैंसी, जो ओ.डब्ल्यू.पी.ए. है, उसकी आप रिपोर्ट पढ़िए। उससे आपको पता चलेगा कि कितने ट्रेड कोर्सेज को उन्होंने आईडेंटिफाई किया है। आज आप कोई भी प्रोडक्ट उठाइये, वह मेड इन चाइना है। उसके पीछे दो कारण हैं। वह प्रोडक्ट यूएस में रिसर्च करके पैटेंटेड हुआ है, किन्तु मैनुफैक्चर्ड इन चाइना है। क्योंकि एक तो वह सस्ता है और दूसरा वहां पर व्यवस्था है। उन्होंने ओर्जिनली इक्विपमैंट मैनुफैक्चरिंग हब बनाया है। भारत में भी वह हब बनाने की जरूरत है. उस इफ्रास्ट्रक्चर की जरूरत है, मैनपावर की जरूरत है और उसके लिए हमें स्किल डेवलपमैंट की जरूरत है।

महोदय, इसलिए मैं कहना चाहता हूं कि कनाडा ने ह्यूमन रिसोर्स एंड स्किल डेवलपमैंट बनाया, नैशनल आक्यूपैशनल क्लासीफिकेशन किया। हमारे यहां अभी तक नहीं हो सका है। हमने यू.के. कमिशन फॉर इम्प्लायमैंट एंड स्किल्स के बारे में तैयारी ही नहीं की है। चाइना में 50 हजार से ज्यादा ट्रेड कोर्सेज आईडेंटिफाइड हैं, जिनकी ट्रेनिंग उन्हें दी जाती है। हम साधारण सी बात करें, तो हम सबके पास स्मार्ट फोन है। सबकी कांस्टीटूएंसी में स्मार्ट फोन है। स्मार्ट फोन को ठीक करने वाले मिस्त्री मिल सकते हैं। मैं हांगकांग एक रिफरबिशिंग युनिट देखने गया। मुझे वहां यह देखकर बहुत आश्चर्य हुआ, मैंने मिस्त्री से पूछा कि एक महीने में कितने स्मार्ट फोन रिफरबिश करते लेते हो। उसने कहा कि प्रति महीना तीन मिलियन फोन रिफरबिश करता हूं। इसका मतलब हुआ तीस लाख फोन। वह पुराने फोन में एक एटमॉसफेयर क्रिएट करके रिफरबिश करता है, उसका सब कुछ बदल देता और वही थर्ड वर्ल्ड कंट्री में बिकता है और लोग खरीदते हैं। इस पर यू.एन की गाइडलाइन है।

युनाइटेड नेशन ने स्किल डैवलपमेंट पर गाईडलाइन्स बनाई हुई हैं और बहुत सहायता देते हैं। हमें चाहिए कि हम गांव-गांव तक 'मेक इन इंडिया' का सपना पूरा करने के लिए कोशिश करें। पहले हम पहचान बनाएं कि हमारे पास जो ग्राहक आएगा वह क्या लेकर आएगा। वह जो लेकर आएगा, उसे न नहीं कहना है और यह नहीं कहना है कि सोचेंगे। हमारे पास उसकी ड्राइंग पढ़ने वाला और उसे इम्पलीमेंट करने वाला आदमी होना चाहिए। माननीय प्रधानमंत्री जी ने यह सपना देश के सवा अरब लोगों के लिए देखा है।

इसे साकार करने के लिए जो संकल्प लाया गया है, मैं इसका पूर्ण समर्थन करता हूं और उम्मीद करता हूं कि यह रोशनी गांव-गांव तक पहुंचेगी। धन्यवाद।

श्री बलभद्र माझी **(नबरंगपुर):** माननीय उपाध्यक्ष जी, आपने मुझे महत्वपूर्ण, संवेदनशील और गंभीर विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं। यह बात सही है कि अगर किसी भी आदमी के पास कोई स्किल, गुण, कौशल नहीं है तो वह आज के जमाने में जी नहीं सकता है। उसे जीने के लिए कुछ न कुछ करना पड़ेगा। यही कारण था कि पुराने जमाने में काम के हिसाब से जातियों की सृष्टि हुई थी। जिस काम में जो प्रवीण है, वही काम करता था। जिसे पूजा, पाठ, पढ़ना आता था, ब्राह्मण बन गया, जो अच्छा युद्ध कर सकता था, क्षत्रिय बन गया। मेरे पूर्व वक्ता ने कहा कि हर गांव सैल्फ सफिशिएंट रहा, वहां नाई, लौहार, मिट्टी का काम करने वाले रहते थे ताकि एक गांव दूसरे पर निर्भर न करे। तब हर कोई आदमी बहुत खुशहाली से आराम से रहता था। आज हम स्किल डैवलपमेंट की चर्चा क्यों कर रहे हैं? जमाना बदल गया है, दुनिया बदल गई है, लोगों की जरूरतें बदल गई हैं, जीवन शैली बदल गई है। अब टैक्नोलॉजी आ गई है। आज हाथ से खेती से मुनाफा नहीं हो सकता है। मैकेनाइज्ड वे में जाना होगा, ट्रैक्टर चलाना पड़ेगा। अब मिट्टी का मटका खरीदने के लिए कोई तैयार नहीं होता है, स्टील का पसंद करते हैं। आज हम प्लास्टिक, मोबाइल, आईपैड के युग में आ गए हैं। सब चीजें बदल गई हैं इसलिए हिंदुस्तान में यह सब हो रहा है। भारत कृषि प्रधान देश है इसलिए यह चर्चा का विषय बन गया है। कृषि भी अब मुनाफे का काम नहीं रहा है। अगर किसी को मौका मिले तो वह कृषि का काम छोड़ना चाहेगा, कोई दूसरा धंधा करना चाहेगा।

महोदय, बेरोजगार की परिभाषा क्या है? अगर कोई पढ़ लिख गया और उसे नौकरी नहीं मिली, तो वह बेरोजगार हो गया। महोदय, मुझे जो आंकड़ा प्राप्त है, सारी राज्य सरकार से लेकर केन्द्र सरकार तक, प्यून से लेकर केन्द्र सरकार के चीफ सैक्रेटरी तक यदि हम आंकड़े मिलाते हैं तो सरकारी नौकरी सिर्फ चार करोड़ के आसपास होती है। 25 करोड़ आबादी में चार करोड़ नौकरी रहती है और मंशा यह रहती है कि कोई थोड़ा पढ़-लिख लिया तो सरकारी नौकरी करना चाहता है। अगर नौकरी नहीं मिली तो या तो कुछ क्रिमिनल एक्टिविटी करेगा, चोरी करेगा या दूसरा धंधा करेगा। हम लोगों ने इस तरह से सिस्टम नहीं बनाया है कि पढ़कर भी कुछ कर सके। पढ़ाई का सिस्टम हमारे यहां ब्रिटिशों के जमाने वाला, क्लर्क बनाने वाला सिस्टम ही चल रहा है। एजुकेशन पॉलिसी के नाम पर किसी भी सरकार ने क्या सोचा है? वही पुराना बी.ए., बी.कॉम. पढ़ो। जिस आदमी ने साइंस पढ़ी, वह क्लेरिकल का काम करेगा। जिसने बी.कॉम की पढ़ाई की, वह आगे जाकर टीचर बनेगा। कोई खेती करेगा तो उसकी अलग से पढ़ाई हो।

जब हम कहते हैं कि 60-70 प्रतिशत लोग खेती पर निर्भर करते हैं तो हमारी शिक्षा नीति क्या ऐसी है कि 60 प्रतिशत हम शिक्षित किसान बना रहे हैं? इस दिशा में हमने कभी नहीं सोचा। किसी भी दिशा में कितने डॉक्टर्स, इंजीनियर्स की जरूरत है, इसकी प्रोपर एनेलिसिस नहीं की गई है और एआईसीटी जैसी संस्था बना दी गई है। उसका परिणाम यह हुआ है कि बिना सोचे समझे उड़ीसा जैसे प्रदेश में आज की तारीख में 110 इंजीनियरिंग कॉलेज हैं जहां 40000 सीट्स हैं। 40000 सालाना अगर इंजीनियर निकलेंगे तो उड़ीसा में तो इतनी नौकरी नहीं हैं। परिणाम यह हो रहा है कि चालीस हजार सीट्स जो हैं, वे तो प्राइवेट में चला रहे हैं, उन्हें तो मुनाफा कमाना है, बच्चों को जबर्दस्ती भर्ती करना है, वह कोई धर्म काज के लिए काम नहीं कर रहे हैं। जबर्दस्ती थर्ड डिवीजन बच्चों को भी लोग उनमें भर्ती करा रहे हैं और परिणामस्वरूप जिन बच्चों का इंटेलीजेंस इंजीनियरिंग के लायक भी नहीं है, वे भी इंजीनियरिंग की पढ़ाई कर रहे हैं। परिणामस्वरूप उनमें से प्रतिदिन इंजीनियरिंग पढ़ने वाला बच्चा उड़ीसा में सुसाइड कर रहा है क्योंकि वह पढ़ नहीं सकता है। लेकिन मां-बाप सोचते हैं कि जैसे बच्चा इंजीनियर बन गया तो लाखों करोड़ों कमा लेगा और परिवार का कल्याण हो जाएगा।

मेरा निवेदन है कि हर चीज के लिए सरकार को प्रोपर एनेलिसिस करनी चाहिए। मेरे जिले में जहां डॉ. की जो बात करेंगे, मैं बताना चाहूंगा कि 24000 लोगों के लिए एक डॉक्टर है। मेरा नवरंगपुर जिला उड़ीसा में है, वहां 24000 आदमी के लिए एक डॉक्टर है। इसलिए यह जो विडम्बना है, ड्राइविंग एक ऐसी चीज है कि आज के दिन में सबसे ज्यादा रोजगार ड्राइविंग के क्षेत्र में ही मिल रहा है लेकिन सरकार की ओर से कोई ड्राइविंग इंस्टीट्यूशन नहीं है। जिसने भी थोड़ी गाड़ी चलानी सीख ली, वह ड्राईवर बन गया और गाड़ी चलाने लगा।

महोदय, आज अकेले दिल्ली में ही यदि आप देखेंगे कि शत प्रतिशत गाड़ी में स्क्रैच लगा हुआ है। कोई एक भी गाड़ी साफ सुथरी नहीं है, यहां तक कि नयी गाड़ी भी ऐसी नहीं है जिस पर स्क्रैच न लगा हो। इसका कारण यह है कि हमने कभी इस दिशा की ओर ध्यान नहीं दिया और कोई ड्राइविंग इंस्टीट्यूशन कभी नहीं खोला। ठीक है कि सरकार ने स्किल्ड डवलपमेंट की तरफ सोचा है लेकिन हर क्षेत्र में कैसे करें? मेरा मानना है कि हर क्षेत्र में प्रोपर एनेलिसिस की जाए कि इस क्षेत्र में इतनी जरूरत है और वहीं पर ट्रेनिंग दी जाए तब जाकर हमारे प्रयास सही मायने में सार्थक सिद्ध होंगे। धन्यवाद।

श्री जगदम्बिका पाल **(डुमरियागंज):** माननीय उपाध्यक्ष जी, इस सदन में हमारे संसदीय कार्य राज्य मंत्री अक्सर स्किल डवलपमेंट की बात किया करते थे और उसकी रूपरेखा पर भी कई बार उन्होंने प्रकाश डाला कि पहली बार कई मंत्रालयों में जो अलग-अलग स्कीम्स चल रही थीं, यह भारतीय जनता पार्टी, एन.डी.ए. की सरकार में माननीय प्रधान मंत्री जी के इनीशिएटिव से यह भारत में पहली बार हुआ। मैं लंच करने के लिए घर चला गया था। मैंने लंच करते हुए देखा कि एक बार हमारे कांग्रेस के सम्मानित नेता खड़गे जी खड़े हुए और उन्होंने कहा कि माननीय मंत्री जी के पास शायद बैग नहीं है तो कहां से यह मंत्रालय चलेगा?

17.00 hrs

मैं घर चला गया था। श्री खड़गे जी, मैं आपका उल्लेख कर रहा हूँ।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे**: जी हाँ, बोलिए।**

श्री जगदम्बिका पाल**: मैंने देखा, जब माननीय खड़गे जी खड़े हुए, तो मैंने सोचा कि शायद डिबेट में भाग ले रहे हैं क्योंकि विधेयक के बाद लंच करने चला गया था। उन्होंने कहा कि मंत्री जी के पास बैग नहीं है, तो यह मंत्रालय कैसे चलेगा या स्किल डेवलपमेंट के संबंध में कुछ नहीं है, तो मैं इससे सहमत हूँ। लेकिन माननीय खड़गे जी भी इस बात से सहमत होंगे कि आज देश में जिस तरह से दुनिया में भारत के बाद चाइना में जो वर्क फोर्स है, यूथ्स हैं, शायद वर्ष 2020 में हम दुनिया के सबसे जवान देश हो जाएं। आज आवश्यकता है, चाहे आप प्रतिपक्ष में बैठें या हम सरकार में बैठें, इस सदन को चिन्ता करनी चाहिए कि आने वाले दिनों में अगर दुनिया के सबसे ज्यादा नौजवान इस देश में होंगे, तो उसको स्किल्ड करके उनके हाथों में रोजगार देने का दायित्व इस सदन का और इस सरकार का होना चाहिए। ऐसा मैं समझता हूँ।**

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे **: जैसा कि सबको मालूम है कि "चिन्ता से चतुराई घटे, दुःख से घटे शरीर, पाप से घटे लक्ष्मी" , जैसा बोला गया, जो लक्ष्मी के पुत्र हैं, यदि उनको सपोर्ट नहीं करेंगे, तो आपका स्किल डेवलपमेंट स्किल में रह जाएगा, वह डेवलपमेंट में नहीं आ पाएगा।**

श्री जगदम्बिका पाल**: मैं आभारी हूँ कि सम्मानीय खड़गे जी को इस बात की चिन्ता है। निश्चित रूप से वे एक जिम्मेदार नेता हैं और उन्होंने इसकी चिन्ता की है। मैं समझता हूं कि जो उनकी चिन्ता है, उसकी चिन्ता हमारे प्रधानमंत्री जी को भी है और हमारी सरकार को है। मैं तो पूरी जिम्मेदारी के साथ केवल उल्लेख करना चाहता हूँ कि अभी 12 पंचवर्षीय योजना के तीन साल गुजरे हैं। 11वीं पंचवर्षीय योजना में हम लोग यूपीए-वन और यूपीए-टू में थे।** As per the 11th Five Year Plan, only 10 per cent of the Indian work force had formal training in the form of higher education, technical education or vocational training. **जिस तरह की ट्रेनिंग थी, चाहे वोकेशनल ट्रेनिंग हो, चाहे टेक्नीकल ट्रेनिंग हो, सभी को मिलकार, इस देश के 10 पर्सेंट यूथ्स को हम अभी 11वीं पंचवर्षीय योजना में स्किल्ड कर पाये हैं। इन तीन वर्षों में, जो 12वीं पंचवर्षीय योजना का है, उसकी स्थिति यह है-** Currently, India has an annual training capacity of 4.3 million which is less than 20 per cent of the industry requirement of 22 million skilled workers a

year. आज भारत जैसे देश को जहाँ पर 22 मिलियन स्किल्ड वर्क फोर्स की जरूरत है, जिनके हाथों में हुनर हो, चाहे आईटीआई द्वारा या वोकेशनल ट्रेनिंग द्वारा हो या फीटर हो, स्मिथ-मैन हो, कारपेंटर हो, किसी भी तरह के मैकेनिक हों, उस प्रकार के 22 मिलियन लोगों की जरूरत है, उनके अगेंस्ट आज 12वीं पंचवर्षीय योजना में, जब से यह सरकार बनी है, 4.3 मिलियन को ही ट्रेन्ड करने की हमारी क्षमता है। यही नहीं, as per estimates, various publicly funded organisations produced 3.5 million trained personnel per annum against 12.8 millions new entrants into the work force every year, thus 9.3 per cent of the work force added is unskilled. मतलब 9.3 मिलियन, हम कहाँ जाएंगे? हम देश में रोज चर्चा करें, लेकिन जो देश के नौजवान हैं, जिनका भविष्य है, जिनके परिवार के लोगों को उम्मीद है कि हमारा बच्चा पढ़ने के बाद, स्किल ट्रेनिंग करने के बाद, कहीं पर उसे इम्प्लॉयमेंट मिलेगा और वह घर में बुढ़ापे का सहारा बनेगा। आज मैं निश्चित रूप से समझता हूँ कि जो माननीय खड़गे जी ने चिन्ता प्रकट की है, उस चिन्ता का समाधान पहली बार भारतीय जनता पार्टी-एनडीए की सरकार ने किया है। मैं समझता हूँ कि वे इस बात से सहमत होंगे। नैशनल स्किल मिशन कारपोरेशन की स्थापना की गयी और वह नौजवानों को ट्रेन्ड करेगी। इसके संबंध में भारत सरकार पॉलिसी बनाएगी, यदि इसके लिए नियम बनाने की जरूरत पड़ेगी तो उसे नैशनल स्किल डेवलपमेंट कारपोरेशन के माध्यम से करेंगे। आज हम कहाँ खड़े हैं? India is placed at 135th place out of 187 countries in Human Development Index as per the Human Development Report 2014 issued by UNDP.

HON. DEPUTY SPEAKER: You have taken five minutes. Please conclude early.

श्री जगदम्बिका पाल: मान्यवर, दो मिनट दे दीजिए।

आज हम दुनिया ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स के 187 देशों में 135वें पायदान पर खड़े हैं। मैं दो-तीन बातों का जिक्र करना चाहता हूं जिससे कांग्रेस के हमारे साथी भी सहमत होंगे कि हमने अभी जनरल बजट में 1500 करोड़ रुपये दीनदयाल उपाध्याय ग्रामीण कौशल योजना में रूरल यूथ के लिए दिए हैं। देश के ग्रामीण यूथ के लिए इस जनरल बजट में 1500 करोड़ रुपये केवल स्किल डेवलपमेंट के लिए दिए हैं। अभी तक हम स्किल ट्रेनिंग के लिए कितना पैसा देते थे? स्किल ट्रेनिंग के लिए हमने बजटरी सपोर्ट में 1500 करोड़ रुपये दिए हैं, निश्चित रूप से इससे लाखों नौजवान तैयार होंगे और उनको रोजगार मिलेगा। इसी तरीके से 150 करोड़ रुपये हमने कौशल विकास योजना में भी दिए हैं, जिससे स्किल डेवलपमेंट बढ़ेगा।

Japan has pledged around $ 3,50,000 dollars for four grassroots projects in India, including setting up vocational training classes for children with disabilities in Delhi and for setting up a community health clinic in a Mizoram village.

आज जापान भी हमारे डिसएबल्ड लोगों के लिए मदद दे रहा है। पहली बार हम इस तरह नौजवानों के लिए करने जा रहे हैं। यदि डिजिटल इंडिया की बात करें, डिजिटल इंडिया प्रोजेक्ट में भी हमने दस लाख लोगों को ट्रेन्ड करने की बात की है। नेशनल डिजिटल लिट्रेसी मिशन ने यह काम करने की बात की है। डिपार्टमेंट ऑफ इलेक्ट्रानिक्स एंड इनफार्मेशन टेक्नोलॉजी इसे लांच करने जा रही है। इसी तरीके से अभी तक 20 मंत्रालयों में कम से कम 80 अलग-अलग प्रोग्राम चल रहे थे, दस प्रतिशत वर्कफोर्स नहीं है। मुझे उम्मीद है कि इस मंत्रालय के तहत, जिसकी जिम्मेदारी प्रधानमंत्री जी ने रूडी साहब को दी है, आने वाले दिनों में हमारी यह परिकल्पना है कि नेशनल स्किल डेवलपमेंट, जो हम 187 ट्रेनिंग पार्टनर्स को लेकर 474 जिलों में 2930 सेंटर्स खोल करके लोगों को ट्रेन्ड करेंगे। उस ट्रेनिंग का मतलब होगा कि in total, we will have over 850 million Indians in the working age group by 2020. This will account for 28 per cent of the global workforce. आने वाले दिनों में हम दुनिया की 28 प्रतिशत वर्कफोर्स को तैयार करने जा रहे हैं। इसके लिए यह मंत्रालय, मंत्री जी और हमारे प्रधानमंत्री जी बधाई का पात्र है।

SHRI PREM DAS RAI (SIKKIM): Thank you, Deputy-Speaker, Sir, for givine me a change to participate.

HON. DEPUTY SPEAKER: You will have to conclude within five minutes.

SHRI PREM DAS RAI: Yes, Sir, I will conclude in five minutes.

This is a very important Resolution that has been brought and I think the hon. Minister must be listening to the views of everybody. It is such an important issue because skill has caught the imagination of not only all of India but it has been echoed and it also resonated with some of the major public policy initiatives of the present Government like 'Make in India' and 'Digital India'.

Let me just recount that I had gone to Japan and I had the opportunity to go to one of their major markets where they sell fresh fish which is then made into products known as 'sushi' and 'sashimi'. I had the pleasure of going into one of the restaurants within the market which was selling the products. There were the chefs who make these products. They were involved in this intricate little work of art of producing these products for the customers, *in situ*, that is immediately it was being done by these chefs. When I inquired about how much time the chefs took to reach this stage of skill, they said it took as much as eight to ten years. This is the kind of work that needs to go behind the skilling process. This is just an example of how one actually acquires skills. It is a long drawn process. This is the way in which we should do it, with a sense of excellence rather than just saying, 'This is a *jugaad* or '*chalta hai*' or 'It is okay'. This is where we need to say that it must reach a level of excellence. Therefore, one of the first things is, it is a question of measure. It is a question of saying whether we can reach that level of excellence in any sectoral skill development programme.That is where - I think, the first thing which, I would like to request the hon. Minister, through you -- we should not lose sight of the fact that if you want to become a super power, if you want to become the manufacturing hub of this country, then we definitely need to look at the issue of measurement and also to say that we need to attain a level of excellence in everything.

I would like to make a second important thing. It is important because innovation will go hand in hand with skills. Why does innovation have to go hand in hand with skills is because of the changing nature of our economy; the changing nature of the requirement of skills and the changing nature of technology. Technology infusion as you might have seen is the highest and the most important is in the area of electronics. That is where, I think, we have to look at when we talk of 'Digital India'. That is why a country like the United Kingdom has advanced in a sense that they have a full Ministry of Innovation. So, I think, one of the things that can happen here is that the hon. Minister could think, why not integrate innovation within his Ministry even if it does not have a caption like 'Ministry of Skill and Innovation? But I think, innovation should become an integral part of the Ministry.

Sir, finally I would like to state that a small State like Sikkim, we had thought in the year 2002 that skills would be required and from that time onwards under the leadership of our Chief Minister Dr. Pawan Chamling, we have actually moved ahead in this field. We have set up a State Institute of Capacity Building. We have instituted many sectoral skills, especially in the area of agriculture and horticulture. This is something that our young people are being paid to do. They are getting a stipend of Rs. 2500 a month and one year skills programme so that they reach a level of excellence.

Sir, with these words I would like to close my arguments and just inform the hon. Minister that this is a hugely important Resolution brought forward by Shri C. R. Patil ji, my fellow colleague here and we need to support this.

Thank you.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल (दमोह) : उपाध्यक्ष महोदय, मैं सबसे पहले पाटिल जी को धन्यवाद देना चाहूंगा कि उन्होंने एक महत्वपूर्ण प्रस्ताव को इस सदन में चर्चा के लिए पेश किया है। मैं अपनी बात श्रद्धेय नेता अटल बिहारी वाजपेयी जी से शुरू करूंगा। उन्होंने जनसंख्या के बारे में एक बात कही थी कि मैं सिर नहीं गिनता, लोगों के हाथ गिनता हूं वह भी हुनर के साथ। उस समय लोगों ने उनकी बात पर ध्यान नहीं दिया। शायद खड़गे जी ने मेरी बात को ध्यान से सुना होगा।

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे: सुना है, अपना हाथ, सबके साथ।

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: क्योंकि अभी बार-बार वह लक्ष्मी की बात कर रहे थे, मैं इस बात को बाद में कहना चाहता था, लेकिन अभी कह देता हूं।

माया तेरे तीन गुण, सुंदर, सुभग, सुभास

अवगुण तोमे एक है सांव न आवे पास।

यह प्रस्तुति है। मैं इसलिए कहना चाहता हूं कि नेशनल स्किल डवलपमेंट पालिसी 2009 में बनी थी। आप ही ने लक्ष्य रखा था कि हम 50 करोड़ लोगों को स्किल डवलपमेंट के आधार पर रोजगार देंगे। इसका समय आपने 2009 से 2022 तक का निश्चित किया था। 12वीं योजना में आपको पांच करोड़ लोगों को रोजगार देना था, जो कि 2017 तक थी। बचे हुए 45 करोड़ लोगों को 2022 तक कैसे आप अपने लक्ष्य की पूर्ति करेंगे, यह आपकी दूर-दृष्टि का सबसे बड़ा पैमाना है। मुझे लगता है कि जब देश के प्रधान मंत्री ने यह कहा, यह सबसे अहम् बात है, क्योंकि जो आपने सोचा था, चाहे जिसने भी लिखकर दिया हो पूर्व यू.पी.ए. सरकार को, मुझे नहीं पता। मैं रूडी जी को धन्यवाद दूंगा कि वह यहां मौजूद हैं। पूर्व प्रधान मंत्री जी ने जो लक्ष्य रखा है, आपने अगर उसे मिनीमाइज़ किया है, तो यह व्यावहारिक बात है कि वास्तव में आपने जमीनी सच्चाई को ध्यान में रखकर इस बात को किया है।

मैं सिर्फ दो उदाहरण यहां देना चाहूंगा। पहला तो यह कि 24 मंत्रालय में स्किल डवलपमेंट का काम होता है। मेरे पास शुभ विभाग की सूची है, जिसमें 91 स्किल डवलपमेंट के काम हैं। लेकिन इनमें से मैं कुछ ऐसे मानता हूं जो बिलकुल निरर्थक हैं, जिनकी जरूरत नहीं है। लेकिन कुछ ऐसे क्षेत्र भी हैं, जिनको आपने पूरी तरह से छोड़ दिया है। रैन वॉटर हार्वेस्टिंग इनएक्टिव है, जो सबसे जरूरी है, वह इनएक्टिव है। उसके बाद बेसिक आर्ट भी इनएक्टिव है। फिशिंग और उससे संबंधित जितना भी क्षेत्र है, जो वास्तव में सबसे जरूरी है, वह इनएक्टिव है। टेक्सटाइल्स और कॉटन में तो ऐसी 5-6 योजनाएं हैं, जहां स्किल डेवलपमेंट का काम होता था, अब वह उद्योग धीमा पड़ गया है, लेकिन उसमें 6 ऐसे क्षेत्र हैं जो पूरी तरह से इनएक्टिव हैं। जिसमें कोई एक्टिविटी नहीं है जो सबसे ज्यादा रोजगार दे सकता है। पोलट्री और बॉयलर फॉर्मिंग जो आम आदमी भी कर सकता है, उसमें स्किल डेवलपमेंट का सिस्टम अनएक्टिव है। हमारे एक बहन हेण्डीक्राफ्ट की बात कह रही थीं, चाहे हमारे बस्तर में हों या कहीं और हो, लेकिन उसका ट्रेनिंग सेंटर इनएक्टिव है, जो सर्वाधिक लोगों को रोजगार दे सकता है, जो हुनरवादियों को हुनर दे सकता है। पैंटिंग, मेहंदी, फिटनेस और एनिमल हसबैंडरी है, मैं गांव से आता हूं, लेकिन यह भी अनएक्टिव है। आपने पांच मिनट का समय दिया था, लेकिन अभी तक पांच मिनट नहीं हुए हैं।

HON. DEPUTY SPEAKER: The Minister has to reply at 5.30 p.m. and there are four to five more Members to speak. You have to adjust your time accordingly.

श्री प्रहलाद सिंह पटेल: **महोदय, मैंने आपसे पहले ही कहा है मैं पांच मिनट में अपनी बात समाप्त कर दूंगा।**

एनीमल हसबैंडरी और कृषि लिखा हुआ है। मैं कहता हूं कि कृषि क्षेत्र होना चाहिए, क्योंकि इसमें बहुत सारे क्षेत्र आते हैं, जिनको फिर से परिभाषित करने की जरूरत है। मैं अंत में सिर्फ इतना ही कहना चाहता हूं कि जब कभी आप हुनर वालों को तकनीक देंगे तो इस देश को लाभ होगा। मैंने अखबार में देखा था कि एक व्यक्ति के हाथ-पैर नहीं है, लेकिन मुंह में दातून दबा कर वह सॉफ्टवेयर बनाने का काम कर रहा है। उसके पास हुनर है, यदि उसको तकनीक मिलेगी तो देश का भला होगा। अगर जरूरतमंद है और वह हुनर सीखता है तो भी देश की जरूरत पूरी होगी, लेकिन ऐसे लोगों को जिनको जरूरत भी नहीं है, उन पर अगर तकनीक और पैसा आप खर्च करेंगे तो इस देश का नुकसान होगा। हमारे एक मित्र कह रहे थे कि इंजीनियरिंग कॉलेज से डिग्री लेने के बावजूद उनको रोजगार नहीं मिलता है, बल्कि पूंजी भी चली जाती है। हम जैसे किसानों की जमीनें बिक जाती है। इस तरह से देश का भला होने वाला नहीं है, इसलिए मैं समझता हूं कि हुनर हो, जरूरत हो, तकनीक हो, प्रशिक्षण हो और पूंजी लगे, साथ ही साथ उसको रॉ मैटीरियल भी मिल जाए तथा बाजार उसको मिलता है तो शायद आपका स्किल डेवलपमेंट सार्थक होगा और देश को मजबूत करने का काम करेगा।

यह विषय तो बहुत अच्छा है, लेकिन मैं चाहूंगा कि ऐसे विषयों पर जरूर सार्थक चर्चा होनी चाहिए और सामूहिक रूप से मैं अपील करूंगा और मंत्री महोदय से भी कहूंगा कि सभी 24 मंत्रालयों के स्किल डेवलपमेंट के प्रयोग हैं वह अगर आपके मंत्रालय में एक साथ हो जाएंगे तो मुझे लगता है कि रिजल्ट जल्दी आएगा। मैं फिर से आपको धन्यवाद देते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। धन्यवाद।

श्री संतोख सिंह चौधरी (जालंधर) : **उपाध्यक्ष महोदय, आपने मुझे एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसक्शन में हिस्सा लेने का मौका दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।**

मैं समझता हूं कि वही देश और प्रांत आगे बढ़ सकता है, जिसके नौजवान ने अच्छी शिक्षा हासिल करे। आज के दौर में टेक्निकल एजुकेशन और स्किल एजुकेशन बहुत महत्व रखती है। मैं पंजाब प्रांत से आता हूं और मुझे वह काला दौर याद है जब एक बहुत भयानक समय एटीज़ के बाद पंजाब में आया। उस समय पंजाब के नौजवान स्किल्ड नहीं थे, उनके पास रोजगार नहीं था तो उन्होंने अपने हाथों में मारू हथियार उठा लिए। उसके बाद एक टेरिज्म का युग पंजाब में शुरू हुआ। बेगुनाह लोगों की हत्याएं हुई और देश की एकता और अखंडता को खतरा पैदा हो गया। मुझे वह दिन भी याद है, मेरे साथ बिट्टू जी बैठे हुए हैं, वर्ष 1992 में उस काले दौर के बाद सरदार बेअंत सिंह के नेतृत्व में कांग्रेस की पहली सरकार बनी। मैं भी उस सरकार में मंत्री बना था और हमने पहली दफा टेक्निकल एजुकेशन को प्रमोट करने का रेवोल्युशनरी दौर प्रारम्भ किया। जो बच्चे, जो नौजवान, जिनके हाथों में फायर आर्म्स थे, उनके हाथों में हमने दस्तकारी के टूल्स दिये और हमने पंजाब को आगे ले जाने का यत्न किया। आज एक महीना हो गया है, बजट पर और इससे पहले माननीय प्रधान मंत्री जी बोले और प्रधान मंत्री जी ने सबसे ज्यादा स्ट्रैस मेक इन इंडिया के ऊपर दिया। यह बहुत अच्छी बात है, इंडिया में बड़े लोग आएं, बड़े-बड़े फॉरेन के लोग हमारी इकोनॉमी में इनवैस्ट करें तो फर्क पड़ेगा। लेकिन मेरा एक सवाल है कि हमारे देश के और हमारे प्रांतों में जो स्माल स्केल इंडस्ट्रीज हैं, जो हमारे डोमैस्टिक उद्योग हैं, उनके बारे में न हमने बजट में सुना और न किसी के भाÂाण में सुनाई दिया। ऐसा क्यों है? क्योंकि मैं समझता हूं कि ग्रोथ रेट तभी बढ़ेगा, जब देश का लघु उद्योग डैवलप करेगा। इसलिए आज जो रिजोल्यूशन लाया गया है, स्किल डैवलपमैन्ट की मार्फत जो नौजवान शिक्षा हासिल करेंगे तो वे काम कहां करेंगे, क्या वे बाहर जाकर काम करेंगे? हमारे प्रांत की यह समस्या है कि जो कारपेंटर है, जो मेसन है, जो थोड़ी सी टैक्निकल शिक्षा हासिल करता है, वह अरब कंट्रीज में चला जाता है, क्योंकि हमारे यहां इम्पलायमैन्ट के एवेन्यूज नहीं हैं। हमारा स्माल स्केल इंडस्ट्रीज सिंक कर रहा है, वह मरता जा रहा है। इसलिए मैं माननीय मंत्री जी और सरकार से विनती करना चाहता हूं कि मेक इन इंडिया से पहले जो हमारे देश का लघु उद्योग है, जहां लाखों-करोड़ों स्किल्ड लेबर हैं या जो दूसरे लोग काम करते हैं, उन्हें डैवलप करें।

महोदय, मैं पंजाब की जालंधर कांस्टीटुएंसी से आया हूं और पंजाब में लगभग 15 लाख माइक्रो और स्माल स्केल यूनिट्स काम कर रही हैं, जिनमें साइकिल इंडस्ट्रीज, मोटर पार्ट्स, स्पोर्ट्स गुड्स, हैंड टूल्स, बॉल्स एंड कास्स, ऑटो पार्ट्स, नट्स एंड बोल्ट्स, कास्टिंग, रबड और लैदर आदि स्माल स्केल इंडस्ट्रीज प्रमुख हैं। ये सब मेरे प्रांत में हैं और इसमें से ज्यादा इंडस्ट्रीज मेरे जालंधर संसदीय क्षेत्र में हैं और हमारे यहां की स्पोर्ट्स इंडस्ट्रीज ने देश में अपना नाम कमाया है। जालंधर को स्पोर्टस इंडस्ट्रीज के नाम से जाना जाता है और वर्ल्ड का जो सबसे बड़ा बल्लेबाज है, वह जालंधर से अपना बैट बनवाता है। अभी भी वर्ल्ड कप में हमारे जिन साथियों ने जीत हासिल की, उनका बल्ला भी जालंधर में बना है। यह एक ऐसी प्रमुख इंडस्ट्री है, लेकिन इस इंडस्ट्री को एक बहुत बड़ा चैलेंज चाइना और

पाकिस्तान से है, क्योंकि वाइना और पाकिस्तान से हम कम्पीट नहीं कर सकते, क्योंकि वहां लेबर बहुत सस्ती है। मैं आपकी मार्फत वित्त मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि जो रॉ मैटीरियल बाहर से आता है, उसके ऊपर एंटी डम्पिंग ड्यूटी लगती है, लेकिन जो यहां से जाता है, उस पर ड्यूटी नहीं लगनी चाहिए, लेकिन उल्टा होता है। यह एक बहुत बड़ी समस्या है कि जो रॉ मैटीरियल है, उस पर एंटी डम्पिंग ड्यूटी न लगे और जो बाहर से मैन्युफैक्चर्ड फिनिश्ड गुड्स आता है, उन पर ड्यूटीज लगनी चाहिए। आज से बीस साल पहले स्माल स्केल इंडस्ट्रीज की एक्साइज ड्यूटी की लिमिट डेढ़ करोड़ थी और आज भी वह डेढ़ करोड है। आज जरूरत इस बात की है कि उसे बढ़ाकर पांच करोड़ रुपये किया जाए। मैं यह निवेदन करना चाहता हूँ कि यह जो स्पोर्ट्स इंडस्ट्री है, इसका जो एक्साइज है, सिर्फ 7 और 8 करोड़ रूपये है। यह सभी बल्लेबाजों को मैटीरियल देती है। मेरी यह गुजारिश है कि इसको एबोलिश किया जाए और मेरे क्षेत्र में एक बड़ा मल्टी स्किल डिवेल्पमेंट इंस्टिट्यूट खोला जाए, जिसमें ये सारी सुविधाएं हों।

श्री मनोज तिवारी (उत्तर पूर्व दिल्ली) : उपाध्यक्ष महोदय, सी.आर. पाटिल साहब कौशल विकास का जो विषय ले कर आए हैं, उस पर आपने मुझे बोलने का मौका दिया है, इसके लिए मैं आपका धन्यवाद करता हूँ। महोदय, यह एक ऐसा मुद्दा है, जो भारत के हर युवा को समृद्ध बना सकता है। सदन का कोई भी व्यक्ति इससे असहमत नहीं हो सकता है। सशंकित हो सकता है कि पता नहीं इसकी सफलता कितनी होगी। लेकिन राजीव प्रताप रूडी जी इस मंत्रालय को संभाल रहे हैं और मुझे लगता है कि यह देश का सबसे महत्वपूर्ण मंत्रालय है क्योंकि यह हर मंत्रालय से जुड़ा हुआ है। मेरे जैसा व्यक्ति अगर यहां खड़ा हो कर कुछ बोल रहा है, महोदय, मैं एक गांव का व्यक्ति हूँ, मैं पढ़ाई से फिजिकल एजुकेशन टीचर हूँ, लेकिन मेरी नौकरी नहीं लगी, मैं गाना गाता था, मुझे पता ही नहीं होता था कि मेरा गाना मुझे एक अच्छी जगह पहुंचा सकता है और मैं एक दिन संसद में भी बोल सकता हूँ। मैं समझता हूँ कि हर व्यक्ति के अंदर छिपा हुआ एक ऐसा स्किल है, जिसको आगे लाने की जरूरत है और निश्चित रूप से कल जैसे हमारे कई साथियों ने कहा कि क्या लुहार का बेटा लुहार, राजमिस्त्री का बेटा राजमिस्त्री, क्या नाई का बेटा नाई ही रहेगा, हम समझते हैं कि भारतीय जनता पार्टी ने संस्थागत रूप से इन सारी चीजों को रखा है। आने वाले समय में इसका पूर्ण लाभ हमारे देश के युवाओं को मिलेगा, यह मेरा विश्वास है।

उपाध्यक्ष जी, मैं एक विषय पर बहुत चिंतित हूँ कि आखिर राजमिस्त्री जैसे लोगों को, नाई जैसे लोगों को, लुहार जैसे लोगों को, हमारे गांव में एक राजमिस्त्री है, जो कि बार बार गांवों में घूम-घूम कर काम करते हैं। मेरी यह चिंता है कि इनको अपने कार्य से विरक्ति क्यों हो रही है? हमारे देश की सरकार और यह सदन उनको सम्मानित कैसे कर सकता है, मुझे लगता है कि अगर इस पर हम काम करेंगे तो अच्छा होगा, क्योंकि हम देखेंगे कि कोई ऐसे राजमिस्त्री को पद्म अवार्ड दिया गया, जिसने बहुत अच्छा किया, किसी ऐसे व्यक्ति को ऐसा राष्ट्रीय सम्मान मिला, जिसके कारण उसको इस कार्य में लगने की प्रेरणा मिले? यह बहुत ही दुखद है कि जब हम टीवी पर देखते हैं कि लोग अपने-अपने बच्चों को परीक्षा में नकल करा रहे हैं। लोग बार-बार मंजिल पर चढ़ कर अपने-अपने बच्चों को नकल करा रहे हैं। जो व्यवस्था संभाल रहे हैं, उनका कितना दोष है, यह तो वे जानें, लेकिन मैं हर माता-पिता और बच्चों को बोलना चाहता हूँ कि डिग्री समृद्धि का आधार नहीं है। आपको हुनर पर आना पड़ेगा। मैं अपनी वाणी को विराम देने से पहले दो-तीन सुझाव देना चाहूंगा। हमारे बड़े भाई के सामान राजीव प्रताप रूडी जी इन पर जरूर ध्यान देंगे। जगह-जगह पर फिल्मों में जो लोग काम करते हैं, जो दिन पर भर सिर्फ क्राउड के रूप में काम करते हैं, उनको सिर्फ 1000-1100 रूपये प्रति दिन मिलता है। लेकिन वे ट्रेंड नहीं हैं। हमारे यहां एक डायलॉग बोलने वाले को पांच हजार रूपये मिलते हैं, लेकिन उनको ट्रेंड करने की व्यवस्था नहीं है। अगर हम फोक म्युजिशियन को ट्रेन्ड करने की जरूरत समझें, एक फोक म्यूजिशियन एक दिन बजाने का पांच से छह हजार रूपया लेता है, लेकिन उनकी ट्रेनिंग की व्यवस्था फोक आधार पर नहीं है। मैं समझता हूँ कि इसके अलग-अलग इंस्टिट्यूट खोले जाएं तो हम इस स्किल डिपार्टमेंट को और भी आगे ले कर जा सकते हैं। हमारे एक सदस्य ने बहुत ही अच्छा कहा कि हम खेती के प्रति आकर्षण कैसे पैदा करें, यह भी हमारे स्किल का एक हिस्सा होना चाहिए। आपने मुझे बोलने मौका दिया और मैं समझता हूँ कि यह विभाग आने वाले समय में भारत के युवाओं को बहुत ही अच्छा दिन दिखाएगा।

महोदय, मैं अपनी वाणी को विराम देते हुए सिर्फ दो लाइन बोलना चाहता हूँ कि जब हमारे यहाँ से विदा होकर बहू जाती है तो वह यही कहती है कि "सोना मत दिहा बाबा, चाँदी मत दिहा, बस हुनरवा दिहा ना, ससुरवा हमके पूजे बस सुनरवा दिह ना। " बहुत-बहुत धन्यवाद।

THE MINISTER OF URBAN DEVELOPMENT, MINISTER OF HOUSING AND URBAN POVERTY ALLEVIATION AND MINISTER OF PARLIAMENTARY AFFAIRS (SHRI M. VENKAIAH NAIDU): I just want to end the suspense. There is no proposal to extend the Session.

श्री राजेश रंजन (मधेपुरा) : महोदय, बड़ा दुःख होता है कि हम गम्भीर विषय पर भी बहुत हल्के रूप में सारी बात करते हैं। जिस देश में और जिस देश को बनाने में किसानों, मजदूरों और जवानों का खून-पसीना बहा हो, जिस देश ने 67 सालों में किसानों, मजदूरों और जवानों का सम्मान न किया हो। स्किल इन्डिया की बात हो, स्किल डेवलपमेंट, स्किल इन्डिया, मेक इन इन्डिया की बात आप सब लोग यहाँ कर रहे हैं।

एक माननीय सदस्य : पप्पू जी, जवानों का बहुत सम्मान हुआ है।

श्री राजेश रंजन: कोई सम्मान नहीं हुआ है, जब वह चर्चा आएगी तो उस पर भी आएंगे, वे सब बातें भूल जाइए। तीन अरब लोगों के पास जितनी सम्पति है, उतनी सम्पति मात्र तीन व्यक्तियों के पास दुनिया में है और एक प्रतिशत लोगों के पास दुनिया की अकूत सम्पति हो, सारी 99 प्रतिशत सम्पति उनके पास है। स्किल इन्डिया और डेवलप इन्डिया की बात हम करते हैं, एक तरफ एफडीआई, मॉल, एक तरफ नौकरी से निकालने की व्यवस्था और दूसरी तरफ धनपतियों के द्वारा हजारों-हजार इंजीनियरिंग और आईटीआई, स्कूल और कॉलेज खोलकर लाखों, हजारों बेरोजगार नौजवानों को रोड़ पर खड़ा करने के लिए छोड़ देना। जिस देश में माँ-बाप जमीन और जेवर बेचकर अपने बच्चों को पढ़ाते हों और कोई ऐसा विभाग और ऐसी फैक्ट्री नहीं है, जहाँ से आज नौजवानों को निकाला न जा रहा हो, जो रोड़ पर न हों, आत्महत्या न कर रहे हों और वहाँ पर नये हुनर की बात, हुनर देने के बाद उसे आत्महत्या करने पर जिस देश में मजबूर कर दिया जाता हो और नये हुनर की बात की जाती है। यह देखकर, सुनकर बहुत दुःख होता है और यह बात कहना जरूरी था। मैं कहना चाहूँगा कि सुई, धागा जैसी चीजें जो गाँव की सड़कों पर मिलती थीं, अनिल अंबानी और मुकेश अंबानी की दुकान में अब मिलने लगी हैं। मैं आग्रह करना चाहूँगा कि पहले से ही बढ़ई, कारपेंटर, मोटर मैकेनिक, पेंटर, राजमिस्त्री आदि ये सारी व्यवस्थाएं इस देश में हैं। मैं अपने मित्र विद्वान मंत्री जी से जानना चाहूँगा कि लोग सीख तो लेंगे, हमारे पास कार है तो हम उसे चलाना सीख लेंगे, लेकिन जो कार चलाना जानता है, उसके पास कार नहीं होगी तो उसके सीखने का क्या फायदा। क्या इसके लिए आपने गाँवों में कोई ऐसी व्यवस्था की है मतलब रोजगार की सुरक्षा की गारन्टी आपके पास क्या है? यह बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। उसे उसके काम की सही मजदूरी कैसे मिले, इसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? यह बहुत जरूरी है। तीसरी बात यह है कि जितने भी हमारे तकनीकी कॉलेज हैं या आई.टी.आई. से सम्बन्धित कॉलेजेज हैं, उनमें जो बच्चे पढ़ने जाते हैं, क्या उनके लिए ऐसी कोई व्यवस्था आप कर रहे हैं, जिसमें कि रोजगार की पूरी गारन्टी उसकी पढ़ाई पूरी होने के बाद वहीं उसके कॉलेज के द्वारा इसकी शुरूआत हो। ताकि उसे आत्महत्या करने पर मजबूर न होना पड़े।

महोदय, मैं अपनी दो-तीन सब्मिशन करके अपनी बात समाप्त करूँगा। मैं आग्रह करूँगा कि जब तक आप उद्योग को बढ़ावा नहीं देंगे, वे कौन से उद्योग हैं, गाँव मे जूट का उद्योग है, यह मेरे यहाँ बिहार में है, मेरे यहाँ केला है, मेरे यहाँ बाँस है, मेरे यहाँ काठ है, जिससे बड़ा-बड़ा सुन्दर घर बनता है। हम आपसे दो-तीन बातें जानना चाहेंगे। फूड प्रोसैसिंग के लिए आप स्किल डैवलपमैंट में क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? हैंडीक्राफ्ट के लिए आप क्या व्यवस्था करने जा रहे हैं? जो किसान सरसों उपजाता है, वह तेल खुद नहीं निकालता, वह उद्योगपति निकालेगा। मैं पॉइंट बताकर खत्म कर रहा हूँ। उसके लिए आप क्या व्यवस्था कर रहे हैं? गांव के कंप्लीट एग्रीकल्चर प्रोडक्ट और फूड प्रोडक्ट्स के लिए आप क्या करने जा रहे हैं, यह बहुत महत्वपूर्ण है। क्लॉथिंग इंडस्ट्रीज़ और हाउसिंग इंडस्ट्रीज़ के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? आइल इंडस्ट्री और फूड प्रोसैसिंग के लिए आप क्या करने जा रहे हैं? यह बहुत महत्वपूर्ण है और जब तक एग्रीकल्चर को आप स्किल डैवलपमैंट से नहीं जोड़ेंगे, तब तक स्किल डैवलपमैंट की योजना और मेक इन इंडिया बेकार होगी। ...(व्यवधान)

उपाध्यक्ष जी, जो गाँवों में फ्लावर है जिसे किसान उपजाता है, उन फूलों से दवाई बनती है, उससे जूस बनता है। तो आप फूट्स के लिए क्या व्यवस्था करेंगे? जो एनिमल प्रोडक्शन है, उसके लिए आप क्या करना चाहते हैं? मैं कहना चाहूँगा कि जब तक किसान को ध्यान में रखकर आप योजना नहीं बनाएँगे,...(व्यवधान) तब तक आप देश को आगे नहीं ले जा सकते। धन्यवाद।

कौशल विकास और उद्यमिता मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री **(**श्री राजीव प्रताप रूडी**):** माननीय उपाध्यक्ष जी, माननीय सदस्य श्री सी.आर.पाटिल जी जो प्रस्ताव लेकर आए हैं, और जिस प्रकार से सदन की रुचि इस विषय पर है और हर सदस्य इसमें भाग लेना चाहता है, मैं बताऊँगा कि इस प्रस्ताव के आने के बाद अभी 30-35 माननीय सदस्यों का नाम वहाँ लंबित है। मैं सदन से आग्रह करूँगा, स्पीकर महोदया ने भी कहा था और मैं आपसे भी कहूँगा कि इस पर एक विस्तृत चर्चा की आवश्यकता है जो सरकारी कामकाज के दौरान हो। यह तो हमारा सौभाग्य है कि सी.आर.पाटिल साहब इस प्रस्ताव को लाए और हम लोग इस पर निजी तौर पर विमर्श कर रहे हैं जिसमें सरकार इनकी बात को सुन रही है। खड़गे साहब ने भी इसमें रुचि दिखाई है और इनका भी यह क्षेत्र रहा है। बार-बार इनकी इस बात पर चिन्ता रही है कि आखिर इतनी बड़ी योजना जो सरकार ने घोषित की है, इसको हम पूरा कैसे करेंगे?

महोदय, मैं एक बात देख रहा था कि जिस प्रकार से भी आप सब लोग कह रहे थे, मैं भी जब इस मंत्रालय में आया तो मुझे लगा कि आखिर में यह क्या है। लेकिन जैसे-जैसे दिन बीत रहे हैं वैसे-वैसे मैं इस मंत्रालय को समझ रहा हूँ। मैं भी आपकी तरह ही एक सांसद हूँ। मैं भी देहात से हूँ और छपरा से हूँ। हमारे लोक सभा के सदस्य जानते हैं कि सब पीड़ा एक तरफ है - अस्पताल में आप डाक्टर को दिखवा लेंगे, लेकिन जो रोज़गार की लंबी कतार हमारे घर के बाहर लगी रहती है, ...(व्यवधान)

HON. DEPUTY SPEAKER: Just a minute Rudy *ji*. Hon. Members, the time allotted for this business is over. We can extend it till the Minister's reply.

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** जिस प्रकार से लोग आकर कहते हैं कि हमें रोज़गार चाहिए, हमारे लिए संभव नहीं है कि इतनी बड़ी संख्या में रोज़गार दिया जाए, क्योंकि सरकारी क्षेत्र में और व्यवस्थित क्षेत्र में जो रोज़गार है, वह मात्र 3 करोड़ के आस-पास है। सवा सौ करोड़ के आस-पास के इस देश में सरकार में हम जो रोज़गार दे पाते हैं, वह लगभग 3 करोड़ है और 1 करोड़ के आस-पास व्यवस्थित क्षेत्र में होगा, जिसको हम ऑर्गनाइज्ड सैक्टर कहते हैं। फिर भी हमारे देश में 120 करोड़ में से जो 97 करोड़ लोग हैं, वह एक बड़ी संख्या है जिसके बारे में चुनौती है।

प्रहलाद पटेल जी ने कहा और बाकी सदस्यों ने कहा कि 2009 में इसकी शुरूआत की गई। उस समय वर्तमान सरकार ने तय किया। आज हम उसको विरोधाभास में कह सकते हैं, लेकिन कहीं तो शुरूआत हुई, आपके समय शुरूआत हुई और उस समय की सरकार ने कहा कि 50 करोड़ लोगों को प्रशिक्षित करना है। It is approximately 500 million people. This came under the National Skill Development Policy which was a policy passed by the Cabinet. It is an ambitious project. It is a fact. But it was rather a big challenge. वहाँ 2009 से चलते-चलते हमने एन.एस.डी.सी. का गठन किया, एन.एस.डी.ए. का गठन किया और वर्तमान में जब नरेन्द्र मोदी जी की सरकार बनी, हमारी सरकार बनी तो माननीय प्रधान मंत्री ने कहा कि यह सचमुच एक चुनौती का क्षेत्र है। जब भी माननीय प्रधान मंत्री से मेरी मुलाकात होती है तो कई बार तो वे कहते हैं कि मैं सब काम अलग रखकर एक काम खुद करना चाहता हूँ और वह कौशल विकास है, स्किल डैवलपमैंट है। अगर किसी भी सांसद या व्यक्ति से पूछा जाए तो हुनर एक शब्द है और इसके बारे में हम लोग सुनते भी आ रहे हैं कि 'हुनर है तो कदर है।' यह एक ऐसा शब्द है जो अपने आप में इस ताकत को प्रमाणित करता है। अभी हमारे मित्र मनोज जी कह रहे थे कि बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो या कहीं भी हो, आखिर परीक्षा के समय यह आपाधापी क्यों? बिहार में तो यह सामान्य है कि एक बच्चे को परीक्षा दिलाने के लिए पूरा परिवार निकल जाता है। पिताजी भी पढ़ते रहते हैं, भाई साहब भी पढ़ते रहते हैं, माताजी भी पढ़ती रहती हैं, सब लोग पढ़ते रहते हैं। गांव के मदद्गार लोग आते हैं। एक व्यक्ति की परीक्षा के लिए कोई खिड़की के ऊपर चढ़ा होता है, कोई गेट के बाहर खड़ा होता है और सब लोग उसे परीक्षा दिलाते हैं, क्योंकि हमने साठ वर्षों में जो परंपरा बनायी है, हमने कहा है कि हमारे लिए हमारी डिग्री आवश्यक है। अगर हम मैट्रिक्युलेट नहीं हों, हम आई.ए. पास नहीं हों, हम बी.ए. पास नहीं हों, तो समाज में एक तो हमारी मान्यता नहीं है और दूसरा हमारे पास रोज़गार नहीं है। जहां से हम लोगों ने शुरूआत की, इसकी कई चीज़ों पर विवाद नहीं किया जा सकता है। जिस सरकार में हम लोगों ने शुरूआत की है कि आखिर में इस पूरे प्रशिक्षण को कामयाब बनाया जा सके। विद्यालय से लेकर फैक्ट्री तक किस मानक के तहत, किस सिलेबस के तहत हम इसको लागू करेंगे, यह तो समझना जरूरी है। इसलिए देश में चार चीज़ें तय हुई। पहली चीज़ को नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क कहते हैं। यह तकनीकी शब्द दिखता है, लेकिन इस बात को तय किया गया है कि पूरे भारत में, चाहे वह सिलाई का प्रशिक्षण हो, गाड़ी मैकेनिक हो, बड़ी फैक्ट्री में काम करने वाला हो, असेम्बली लाइन पर काम करने वाला हो, फॉरक्लिफ्ट ऑपरेटर हो, मेसन हो, प्लंबर हो, जो भी आपकी आंखों के सामने दिखता हो, उसकी पढ़ाई का एक सिलेबस होगा। जैसे हम लोग क्लास-वन से लेकर क्लास-टू, क्लास-थ्री, क्लास-फोर, क्लास-फाइव में जाते हैं और पढ़ाई करते हैं, इसी तरह से हर चीज़ के लिए, चाहे वह कृषि के क्षेत्र में हो, हेल्थ के सेक्टर में हो, जो भी सामान्य सिलेबस के बाहर की चीज़ें हैं, हर चीज़ों का एक सिलेबस बनना चाहिए। प्लंबर बनने के लिए आपको क्या करना होगा, ड्राइवर बनने के लिए क्या करना होगा, यह सब तय होगा। हम लोग उसकी मान्यता सरकार के बाहर ले गए हैं। आज तक हम लोग समझते हैं कि सरकारी संस्था ही सर्टिफिकेट्स देती है।...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन**:** यह बनने के बाद वह कहां जाएगा?

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** माननीय सदस्य, मैं सब बता रहा हूं।...(व्यवधान)

यह नेशनल स्किल्स क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क है। जैसा मैंने पहले भी कहा था कि जैसे एक वेल्डर होता है तो हम सब लोग यह समझते हैं कि यह वेल्डर है। लेकिन एक वेल्डर वह होता है, जो बड़े-बड़े कारखानों में जो गाड़ियां बनती हैं, तो वह अपना टॉर्च लेकर आता है और अपनी वेल्डिंग मशीन से छः जगह छोटी-छोटी वेल्डिंग करता है। उसके बाद फिर दो मिनट में उस गाड़ी की चेसिस आगे बढ़ जाती है। एक वेल्डर होता है, जो बड़ी-बड़ी गैस पाइपलाइन पर काम करता है, जिसमें उसका टॉर्च अलग होता है। उसमें वेल्डिंग का तरीका अलग होता है। वह भी वेल्डर होता है। उसका मानक अलग होता है। एक वेल्डर होता है, जो समुद्र के भीतर जाता है और उसके अंदर जो ऑयल रिग्स होते हैं, जहां से तेल निकाला जाता है, उसके पाइप की वेल्डिंग करता है। उसकी क्वालिफिकेशन यह है कि उसे गोताखोर भी होना पड़ेगा और साथ-साथ समुद्र के भीतर जाकर वेल्डिंग का काम भी करना पड़ेगा। हर चीज़ का एक मानक तैयार करना है और नेशनल स्किल डेवलपमेंट एजेंसी द्वारा इस काम को बड़े पैमाने पर किया जा रहा है।...(व्यवधान)

SHRI BHARTRUHARI MAHTAB: Another important Resolution is there. It should not be lapsed.

HON. DEPUTY SPEAKER: Yes, we will take it very soon.

SHRI RAJIV PRATAP RUDY: Sir, I have taken note of it and that is why I have requested the hon. Members, in case this is required – hon. Speaker also mentioned –we will take it in the next Session. But meanwhile, I will just try to make my reply very short so that the Members can have a brief answer.

श्री भर्तृहरि महताब **:** आपकी मुश्किल कम हुई या नहीं?

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** बहुत कम हो गयी।...(व्यवधान)

श्री राजेश रंजन**:** चैम्बर मिला या नहीं?...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** माननीय सदस्य, आप जिस बात की चर्चा कर रहे हैं, उसे मैं समझ सकता हूं। ऐसा बिल्कुल नहीं है।...(व्यवधान)

महोदय, खड़गे साहब ने कहा कि इसके लिए हमारे पास पैसा नहीं है। हमारे पास पर्याप्त पैसा है। सरकार ने और माननीय प्रधान मंत्री जी ने कहा है कि इस क्षेत्र में जितने पैसे की आवश्यकता होगी, देश के कौशल विकास के लिए हम देंगे। इसलिए हमें इस बात की चिंता नहीं है। लेकिन, हमें इस बात को ताकत बनाना है, हमें इस बात का तरीका बनाना है कि आखिर आप सांसदों के क्षेत्र में यह किस प्रकार से पहुंचे और इसकी एक बड़ी शृंखला कैसे बनायी जाए ताकि हम अपने नौज़वानों की मदद कर सकें।

महोदय, इस देश में जो अभी वर्तमान वर्कफोर्स है।...(व्यवधान)

श्री मल्लिकार्जुन खड़गे **:** आपको इसे कृषि क्षेत्र में करना होगा।...(व्यवधान)

श्री राजीव प्रताप रूडी **:** माननीय सदस्य, मैं जानता हूं कि आप साधन के बारे में कह रहे हैं। अगर कोई तीन महीने का कोर्स हो, चार महीने का कोर्स हो, जब उसके खर्च की बात होती है तो किसी भी व्यक्ति को कौशल योग्य बनाने में, अलग-अलग क्षेत्रों में जो अनस्किल्ड वर्क फोर्स है, उसके लिए लगभग दस हजार रुपये की खर्च है। मैं जानता हूं कि यह कितनी बड़ी चुनौती है। आज इस देश

में लगभग 500 मिलियन लोग अन-ऑर्गेनाइज्ड वर्कफोर्स में हैं। इसमें 54औ लोग कृषि क्षेत्र में है। वर्तमान में कृषि को थोड़ा अलग रखते हैं, फिर भी नॉन एग्रीकल्चरल वर्कफोर्स लगभग 250 मिलियन है, यानि कि 25 करोड़। उस 25 करोड़ लोगों को, यदि हमें प्रत्येक व्यक्ति को, जो गांवों में हैं, सड़कों पर हैं, उन्हें प्रशिक्षण देना है और उनके लिए यदि दस हजार रुपये की आवश्यकता हो, और अगर हम 25 करोड़ को दस हजार रुपये से गुना करें तो हमें लगभग पांच लाख करोड़ रुपये अगले पांच वर्षों में चाहिए। यह बड़ा एमाउन्ट है। यह सच्चाई है कि हमें इसकी आवश्यकता है। हमें लगभग 1 लाख करोड़ रुपये प्रत्येक चाहिए। हम प्रधानमंत्री जी से बात कर रहे हैं कि किस माध्यम से इसे पूरा किया जाये। हम सी.एस.आर. और टैक्स इन्जैम्पशन की तरफ जा रहे हैं। हम कोशिश कर रहे हैं कि जो बड़ा गैप है उसको भर कर, इस देश में संसाधन को पूरा करें।

कठेरिया साहब कह रहे थे कि चिंता कहां है? चिंता वहां है कि हम 66 वर्ष के बाद कहां खड़ा हैं? यह जानना बड़ा जरूरी है। जर्मनी के पूरे वर्कफोर्स का 74 फीसदी लोग आज प्रशिक्षित हैं। Eighty per cent of the workforce in Japan is skilled. In China, with a population of around 1.4 billion, 47 per cent of its workforce is skilled. In Australia, this figure is 60 per cent; in UK, it is 68 per cent. Similarly, in South Korea, 96 per cent of its workforce is skilled. In India, just two per cent of its workforce is skilled. If this is two per cent, it is a real challenge. We have just started. We are late but we not disappointed; we are not disheartened. We have to take it यह विषय हर व्यक्ति को प्रभावित कर रहा है।

जगदम्बिका पाल जी ने यंग वर्कफोर्स के बारे में कहा है। हम "मेक इन इंडिया" की बात कर रहे हैं। आज जी.डी.पी. में विभिन्न सैक्टरों का योगदान देखें। Today, the maximum training, which is taking place in India is in the services sector, in hospitality, in tourism. जब तक हम मैन्यूफैक्चरिंग के तरफ नहीं बढ़ेंगे तब तक ऐक्चुअल वेल्थ क्रिएट नहीं होगा। मैन्यूफैक्चरिंग की तरफ जाने के लिए निवेश की जरूरत है, बड़े फैक्टिरयों से संबंद्ध करने की जरूरत है, क्योंकि आज इंडस्ट्रीयल जी.डी.पी. 24-25 प्रतिशत है, उसमें 12 प्रतिशत मैन्यूफैक्चरिंग है, जिसको हमें 20-22 प्रतिशत तक पहुंचाना है। एग्रीकलचर एलाइड सैक्टर लगभग 14 प्रतिशत है। हर क्षेत्र में विकास करने की आवश्यकता है।

अगर हम मान कर चलें कि हमारा सकल घरेलू उत्पाद 8-9 प्रतिशत तक रहेगा। वर्ष 2022 तक इंफ्रास्ट्रक्चर क्षेत्र में 10 करोड़ प्रशिक्षित लोगों की आवश्यकता है। ऑटो और ऑटोमोटिव केयर में, गाड़ी चलाने से लेकर गाड़ी निर्माण के क्षेत्र में, लगभग सवा तीन करोड़ लोगों की आवश्यकता है। बिल्डिंग कंस्ट्रक्शन में सवा तीन करोड़ लोगों की आवश्यकता है। हेल्थ केयर सैक्टर में, मैं नर्सेज की बात नहीं कर रहा हूं, उनके नीचे जो वार्ड अटैन्डेन्ट होते हैं, उनकी आवश्यकता इस देश में लगभग सवा तीन करोड़ है। देश का सबसे बड़ा इम्प्लॉयमेन्ट का क्षेत्र टेक्सटाइल है, उसमें दो करोड़ लोगों की आवश्यकता है। अगर उन्हें हम डिमाण्ड से जोड़ कर देखें तो यह तभी पूरा हो पायेगा जब हम लोगों को प्रशिक्षण दे पायेंगे।

हमने रिसोंसेज के बारे में बात की है। चिंता कहा हैं? मुझे लगता है कि अभी सरकार ने देखा है कि अभी हम लगभग साढ़े छः हजार से सात हजार करोड़ रुपए विभिन्न मंत्रालयों में योजना वाला कर खर्च कर रहे हैं। उनमें से चार मंत्रालय को लिया गया है, जिनमें से श्रम मंत्रालय को बड़ी पूंजी दी गयी थी।

वर्ल्ड बैंक ने एक इंडीपेन्डेन्ट असेसमेन्ट किया है और यह पाया गया है कि आज की तारिख में जो हमारी प्रशिक्षण की व्यवस्था है उसमें 100 लोगों को प्रशिक्षण दिया जा रहा है तो वर्तमान व्यवस्था के तहत उन 100 प्रशिक्षित लोगों में मात्र 27 प्रतिशत लोगों को ही रोजगार मिल पा रहा है, यह बड़ी चिंता की बात है। आज की व्यवस्था में प्रशिक्षित, जिन 27 प्रतिशत लोगों को रोजगार मिल रहा है, एक वर्ष के बाद उनमें से 60 प्रतिशत लोग नौकरी से बाहर हो जाते हैं। इसी चुनौती को देखते हुए भारत सरकार ने तय किया है कि पूरे विषयों का मानक तैयार करके, हम जो भी प्रशिक्षण दें कि उनकी योग्यता ऐसी हो कि प्रशिक्षण के बाद उन्हें रोजगार मिल जाय, इस बात को सुनिश्चित करने के लिए इस मंत्रालय का गठन किया गया है। हमारे लिए सबसे बड़ी चुनौती यह है।

महोदय, एक सर्वेक्षण किया था कि आज जो एम.बी.ए. ग्रैजुएट निकलते हैं, उनमें से मात्र 10 प्रतिशत एम.बी.ए. ग्रैजुएट इम्प्लॉबल हैं, यानि कोई कम्पनी उनको रखने के लिए तैयार है। जो इंजीनियरिंग ग्रैजुएट इस देश में निकलते हैं, उनमें 100 में 17 प्रतिशत ऐसे लोग हैं, जिनको हम अपने या कम्पनियां रोजगार के लिए ले सकते हैं। यह सच्चाई है। आखिर ऐसी डिग्री का क्या मतलब है?

एक माननीय सदस्य ने ऐसपिरेशन के बारे में कहा है। आज इश्तेहार में निकलता है कि मेरा होने वाला दामाद बी.ए. एम.ए. डॉक्टर या इंजीनियर हो, हम माननीय मोदी जी के सरकार में उस दिन के इंतजार में हैं, जिस दिन अखबारों में इश्तेहार हो कि मेरा होने वाला दामाद वीफ प्लम्बर, वीफ कारपेन्टर है, और वह मेरा दामाद बनेगा जिसकी सैलरी 1 लाख रुपये होगी। यह ऐसपरेशन बदलना है क्योंकि उसकी मान्यता नहीं हो पा रही है। आज व्यक्ति के पास हुनर है, लेकिन उसके हुनर की पहचान नहीं बन पा रही है। यह शैक्षणिक क्षेत्र में बड़ा परिवर्तन करने के बाद हो सकता है। यह कैसे हो सकेगा, हम बताएंगे।

अगर विश्व का नक्शा देखें तो पेरू एक देश है। वह यहां से 17 हजार किलोमीटर दूर साउथ अमरीका में है। पता नहीं जाने में कितना समय लगेगा। वहां की ऐम्बेसी ने हमें सूचित किया कि भारत से यहां की कम्पनियां वीज़ा मांग रही हैं। हमने छानबीन की कि पेरू से 17 हजार डाक्टर आ रहे हैं, इंजीनियर आ रहे हैं, रॉकेट साइंटिस्ट आ रहे हैं। उस देश में मात्र ढाई सौ भारतीय हैं। पेरू में इंग्लैंड और कनाडा की तरह भारत के लोग नहीं हैं। शायद उनकी भाषा भी अलग होगी। पता चला कि वहां से फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर, जो आप रोज देखते हैं, उसका वीज़ा कम्पनियां ले रही हैं। लॉग होल्ड ड्रिल ऑपरेटर के लिए वीज़ा दे रही हैं ताकि भारत में आकर वे चलाएं। इस देश में 66 साल बाद बड़े डम्पर्स चलाने के लिए, लॉग होल्ड ऑपरेटर्स चलाने के लिए, फोर्क लिफ्ट ऑपरेटर्स चलाने के लिए भारत में 17 हजार किलोमीटर दूर से लोग आकर वेतन कमाकर चले जाएं, यह चिन्ता का विषय है। मैं आपको यह उदाहरण इसलिए दे रहा हूं कि आखिर हम इस चुनौती को कैसे पूरा करेंगे।

ऑस्ट्रेलिया की आबादी वैसे ही बहुत कम है। जैसे हमारे यहां बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश है, वैसे ही उनका एक प्रांत है जिसकी आबादी 1.10 लाख के आसपास है। वहां 1,032 क्वालीफिकेशन पैक्स हैं, यहां तक कि हमारे यहां जो आईपीएस बनता है, पुलिस की नौकरी करता है, एसपी, डीएसपी बनता है, उनके यहां आईपीएस ऑफिसर की बहाली के लिए सबसे पहले स्किल ट्रेनिंग होती है, वह स्किल इंस्टीट्यूट में जाता है। सिपाही की ट्रेनिंग का भी स्किल टैस्ट होता है, क्वालीफिकेशन पैक होता है। वह शिक्षा नहीं होती, यूपीएससी का इम्तहान नहीं होता। यह देखा जाता है कि बचपन से लेकर थोड़ी पढ़ाई, उसके बाद प्रशिक्षण, यह अच्छा सिपाही बनेगा, अच्छा दरोगा बनेगा या अच्छा एसपी बनेगा। यह उसके शिक्षा काल में तय हो जाता है। जब वह निकलकर आता है तो उसे सरकार वहां नौकरी देती है। National Skills Qualification Framework has decided that till 2016 every employment or every organisation which is giving skill development, has to align with the National Skills Qualification Framework. यह भी तय हुआ है कि वर्ष 2020 तक भारत सरकार की तमाम नियुक्तियों में आपके सर्टीफिकेट में अगर स्किल नहीं होगा तो आपकी योग्यता सरकारी नौकरी के लायक नहीं होगी। यह बड़े परिवर्तन की व्यवस्था की जा रही है। मुझे लगता है कि आने वाले दिनों में यह बहुत दूर तक जाएगा।

महोदय, समय कम बचा हुआ है। हम अभी तक सरकार से बड़े जुड़े रहते हैं। सैक्टर स्किल काउंसिल जिसकी आपके समय में शुरूआत हुई, उसमें 33 सैक्टर स्किल काउंसिल हैं। अगर मैं ऑटोमोटिव केयर में हूं, टायर इंडस्ट्री, तैदर इंडस्ट्री में हूं, तो मुझे इंडस्ट्री में काम करने के लिए किस प्रकार का व्यक्ति चाहिए, शायद आईटीआई पर उन्हें विश्वास नहीं है, इंडस्ट्री तय कर रही है कि हमारा क्वालीफिकेशन पैक क्या हो। मैं उदाहरण के तौर पर बताना चाहता हूं। मान लें मैं पॉयलट हूं। पॉयलट के रूप में जहाज उड़ाना जानता हूं, लेकिन साथ ही नेविगेशन भी जानता हूं। वह एक अलग कोर्स होता है। मैं एयर ट्रैफिक कंट्रोलर का काम भी जानता हूं क्योंकि उसमें कम्युनिकेशन करता हूं। यह मिलाकर क्वालीफिकेशन पैक है। एयर ट्रैफिक कंट्रोलर अलग से भी अपनी नौकरी कर सकता है। नेविगेशन, मेट्रोलॉजी में भी व्यक्ति अलग से नौकरी कर सकता है। पॉयलट अलग से भी प्रशिक्षण का काम कर सकता है। इसके तहत 33 सैक्टर स्किल काउंसिल्स बनाए गए हैं। सैक्टर स्किल काउंसिल हमारे और आपके लोगों का नहीं हैं, यह इंडस्ट्री का है और इंडस्ट्री बॉडी तय करती है कि इतने हजार लोगों को इम्प्लॉयमैंट दिलाने के लिए आखिर किस प्रकार की ट्रेनिंग दी जाए। उसके मोबिलाइजेशन का काम करती है, उसकी ट्रेनिंग के लिए सिलेबस बनाती है, उसको हम लोग क्वालिफिकेशन पैक कहते हैं। उस सिलेबस का एसेसमेंट का तरीका होता है, वह एसेसमेंट करती है और फिर सर्टिफिकेट जारी करते हैं। हमारा प्रयास है कि देश की हर फैक्ट्री चाहे वह पब्लिक सेक्टर में हो या प्राइवेट सेक्टर में हो, उसकी मान्यता बढ़ाने के लिए क्वालिफिकेशन पैक के तहत सेक्टर स्कील कॉउंसिल का सर्टिफिकेट देश में सर्वोत्तम हो तभी इस देश में कौशल विकास दिए जाने वाली डिग्री की अहमियत स्थापित हो सकती है।

महोदय, कल सुषमा स्वराज जी के साथ मेरी बैठक थी। सुषमा जी ने कहा कि मिडल ईस्ट में लगभग छह हजार लोग जेलों में बेद है। कुछ लोग यहां से रिक्रूट करके ले जाते हैं, हाउस हेल्पर और कई तरह के काम के लिए ले जाते हैं, उनकी बेसिक ट्रेनिंग नहीं होती है। उन्हें ड्राइवर बना कर ले जाते हैं, अगर ड्राइवर से एक्सीडेंट हो जाए, सऊदी अरब में एक गरीब आदमी को फांसी की सजा दी गई है, उनका कानून अलग है। उनका उचित तरीके से प्रशिक्षण नहीं हुआ, अब हमने तय किया है कि जब तक स्कील ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट नहीं होगा हम भारत से बाहर जाने वाले व्यक्ति को अनुमति नहीं देंगे। हम उसे जेल जाने की अनुमति नहीं देंगे। हम लोगों को डिफेंस में ट्रेनर की जरूरत है। डिफेंस सेक्टर से 50 हजार लोग जो बीस साल की सेवा के बाद रिटायर होते हैं। हमारी डिफेंस मिनिस्टर से बात हुई है, हम 50 हजार लोगों को जब उनकी नौकरी का अंतिम साल होगा उनको ट्रेनिंग दिलाकर या तो वे ट्रेनर के रूप में बाहर आएंगे या इन्टरप्रन्यूर के रूप में बाहर जाएंगे। देश में फौजियों की एक बड़ी भूमिका है। प्रधानमंत्री जी ने अपने भाषण में कहा था। इंडियन रेलवे देश का सबसे बड़ा उपक्रम है, उसके पास शेड है, प्लेटफार्म है, पानी है, बिजली है। ...(व्यवधान) Sir, I

have to conclude. ...(*Interruptions*) I will come back to you. इंडियन रेलवे के पास एक चीज है जो किसी भी संस्था के पास नहीं है, वह है ऑप्टिकल फाइबर नेटवर्क, रेलवे के पास 47,000 किलोमीटर का ऑप्टिकल् फाइबर नेटवर्क है। गांव-गांव के कैचमेंट एरिया में कम्प्यूटर लगाने के लिए वहां वर्चुअल ट्रेनिंग की व्यवस्था करा सकते हैं। रेलवे वहां पहुंचती हैं जहां सड़क भी नहीं पहुंचती है। हम नए-नए विचार लेकर आ रहे हैं। उसमें सदन का समर्थन चाहिए। खड़गे जी, अधीर रंजन चौधरी जी, मुनियप्पा जी और भतृहरि महताब जी का समर्थन चाहिए, यह बड़ा काम है और सभी का काम है, हुनर है तो कदर है। I have got many more things. I do not have the time. I want Mr. Nishikant Dubey to introduce his next Resolution. So, I would request Mr. Patil to withdraw it. The Government is fully sensitive to it and I would request him to withdraw it.

श्री सी.आर. पाटील **(**नवसारी**) :** उपाध्यक्ष महोदय, जो प्रस्ताव मैं लेकर आया था, उस पर सभी साथियों ने अपने विचार प्रकट किए और जिस तरह से मंत्री जी ने जिस तरीके से काम हो रहा है उसके बारे में बताया। मैं अपना प्रस्ताव विड्रा करता हूं।

HON. DEPUTY SPEAKER: Are you withdrawing your Resolution?

SHRI C.R. PATIL: Sir, I withdraw my Resolution.

HON. DEPUTY SPEAKER: Is it the pleasure of the House that the Resolution moved by Shri C.R. Patil be withdrawn?

The Resolution was, by leave, withdrawn.

17.58 hrs